

प्रधानमंत्री कार्यालय

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में "क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड" विषय पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य (23 जनवरी, 2018)

प्रविष्टि तिथि: 23 JAN 2018 5:57PM by PIB Delhi

His Excellency the President of the Swiss Federation,

Honourable Heads of State and Government,

World Economic Forum के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष श्री क्लॉज़ श्वाब,

विश्व के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित उद्यमी, उद्योगपति और CEOs

मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों,

नमस्कार।

दावोस में World Economic Forum की इस अड़तालीसवीं वार्षिक बैठक में शामिल होते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है। सबसे पहले मैं श्री क्लॉज़ श्वाब को उनकी इस पहल पर और World Economic Forum को एक सशक्त और व्यापक मंच बनाने पर बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। उनके vision में एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है जिसका उद्देश्य है दुनिया के हालात सुधारना। उन्होंने इस एजेंडा को आर्थिक और राजनीतिक चिंतन से बहुत मज़बूती के साथ जोड़ दिया है। साथ ही साथ हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत-सत्कार के लिए मैं Switzerland की सरकार और उसके नागरिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

Friends,

दावोस में आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा सन् 1997 में हुई थी, जब श्री देवे गौड़ा जी यहाँ आए थे। 1997 में भारत का GDP सिर्फ़ 400 billion dollar से कुछ अधिक था। अब दो दशकों बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है। उस वर्ष इस फोरम का विषय "Building the Network Society" था। आज, 21 साल बाद technology और digital age की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को देखें तो यह विषय सदियों पुराना जान पड़ता है। आज हम सिर्फ़ network society ही नहीं, बल्कि big data (डेटा), artificial intelligence तथा Cobots (कोबोट) की दुनिया में हैं। 1997 में EURO मुद्रा प्रचलित नहीं हुई थी। और Asian financial crisis का कोई अता-पता नहीं था, ना ही BREXIT के आसार थे। 1997 में बहुत कम लोगों ने ओसामा बिन लादेन के बारे में सुना था और Harry Potter का नाम भी अनजाना था। तब शतरंज के खिलाड़ियों को computer से हारने का गंभीर खतरा नहीं था। तब Cyber Space में Google का अवतार नहीं हुआ था।

और यदि 1997 में आप internet पर "Amazon" शब्द टूँटते तो आपको नदियों और घने जंगलों के बारे में सूचना मिलती। उस जमाने में tweet करना चिड़ियों का काम था, मनुष्यों का नहीं। वह पिछली शताब्दी थी।

आज, दो दशकों के बाद हमारा विश्व और हमारे समाज बहुत सी जटिल networks के network हैं। उस जमाने में भी दावोस अपने समय से आगे था, और यह World Economic Forum भविष्य का परिचायक था। आज भी दावोस अपने समय से आगे है।

इस वर्ष फोरम का विषय – "Creating a shared Future in a Fractured World" है। यानि दरारों से भरे विश्व में साझा भविष्य का निर्माण। नये-नये बदलावों से, नई-नई शक्तियों से आर्थिक क्षमता और राजनैतिक शक्ति का संतुलन बदल रहा है। इससे विश्व के स्वरूप में दूरगामी परिवर्तनों की छवि दिखाई दे रही है। विश्व के सामने शांति, स्थिरता और सुरक्षा को लेकर नई और गंभीर चुनौतियां हैं।

Technology driven transformation हमारे रहने, काम करने, व्यवहार, बातचीत और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों और राजनीति तथा अर्थव्यवस्था तक को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। Technology के जोड़ने, मोड़ने और तोड़ने – तीनों आयामों का एक बड़ा उदाहरण Social media के प्रयोग में देखने को मिलता है। आज Data (डेटा) सबसे बड़ी संपदा है। Data (डेटा) के global flow से सबसे बड़े अवसर बन रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौतियां भी। Data के पहाड़ के पहाड़ बनते जा रहे हैं। उन पर नियंत्रण की दौड़ लगी हुई है। क्योंकि, ऐसा माना जा रहा है कि जो Data को काबू में रखेगा वही

भविष्य पर अपना वर्चस्व बनायेगा।

इसी तरह cyber security और nuclear safety के क्षेत्रों में भी तेजी से बदलती हुई technology और विनाशकारी शक्तियों के विस्तार से पहले से चली आ रही चुनौतियाँ और भी गंभीर हो गयी हैं। विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नये आयामों में एक ओर तो मानव को समृद्धि के नये रास्ते दिखाने की क्षमता है। वहीं दूसरी ओर, इन परिवर्तनों से ऐसी दरारें भी पैदा हुई हैं जो दर्द भरी चोट पहुंचा सकती हैं। बहुत से बदलाव ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए शान्ति और समृद्धि के रास्ते को दुर्गम ही नहीं दुःसाध्य बना दिया है। ये fractures, ये divides और ये barriers विकास के अभाव की हैं, गरीबी की हैं, बेरोजगारी की हैं, अवसरों के अभाव, और प्राकृतिक तथा तकनीकी संसाधनों पर आधिपत्य की हैं। इस परिवेश में हमारे सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मानवता के भविष्य और भावी पीढ़ियों की विरासत के लिए समुचित जवाब मांगते हैं।

क्या हमारी विश्व-व्यवस्था इन दरारों और दूरियों को बढ़ावा दे रही है? वे कौन सी शक्तियाँ हैं जो सामंजस्य के ऊपर अलगाव को तरजीह देती हैं, जो सहयोग के ऊपर संघर्ष को हावी करती हैं? और हमारे पास वे कौन से साधन हैं, वे कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिये हम इन दरारों और दूरियों को मिटाकर एक सुहाने और साझा भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं?

Friends,

भारत, भारतीयता और भारतीय विरासत का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए इस फोरम का विषय जितना समकालीन है उतना ही समयातीत भी है। समयातीत इसलिए क्योंकि भारत में अनादिकाल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आये हैं, उसे तोड़ने में नहीं, उसे बांटने में नहीं। हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गये ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने कहा: "वसुधैव कुटुम्बकम्"। यानि पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्त्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं, हमारी नियतियाँ एक साझा सूत्र से हमें जोड़ती हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की यह धारणा निश्चित तौर पर आज दरारों और दूरियों को मिटाने के लिए और भी ज्यादा सार्थक है। लेकिन आज एक गंभीर बात यह है कि इस काल की विकट चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे बीच सहमति का अभाव है। परिवार में जहाँ एक ओर सौहार्द और सहयोग होता है वहीं कुछ न कुछ मतभेद और झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन परिवार का प्राण, उसकी प्रेरणा यही भावना होती है कि जब साझा चुनौतियाँ सामने आये तो सब लोग एकजुट होकर उनका सामना करते हैं, और एकजुट होकर उपलब्धियों और आनंद के हिस्सेदार बनते हैं। परन्तु चिंता का विषय है कि हमारे विभाजनों ने, दरारों ने इन चुनौतियों के खिलाफ मानव जाति के संघर्ष को और भी कठिन, और भी कठोर बना दिया है।

Friends,

जिन चुनौतियों की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ उनकी संख्या भी बहुत है और विस्तार भी व्यापक है। यहां पर मैं सिर्फ तीन प्रमुख चुनौतियों का जिक्र करूंगा जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे पैदा कर रही हैं। पहला खतरा है Climate Change का। Glaciers पीछे हटते जा रहे हैं। आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है। बहुत से द्वीप डूब रहे हैं, या डूबने वाले हैं। बहुत गर्मी और बहुत ठंड, बेहद बारिश और बाढ़ या बहुत सूखा - extreme weather का प्रभाव दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। इन हालात में होना तो यह चाहिए था कि हम अपने सीमित संकुचित दायरों से निकलकर एकजुट हो जाते। लेकिन क्या ऐसा हुआ? और अगर नहीं, तो क्यों? और हम क्या कर सकते हैं जो इन हालात में सुधार हो। हर कोई कहता है की carbon emission को कम करना चाहिए। लेकिन ऐसे कितने देश या लोग हैं जो विकासशील देशों और समाजों को उपयुक्त technology उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराने में मदद करना चाहते हैं।

आपने अनेक बार सुना होगा भारतीय परम्परा में प्रकृति के साथ गहरे तालमेल के बारे में। हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में मनुष्यमात्र को बताया गया- "भूमि माता, पुत्रो अहम् पृथ्व्याः" यानि, we the human are children of Mother Earth. यदि हम पृथ्वी की संतान हैं तो आज मानव और प्रकृति के बीच जंग-सी क्यों छिड़ी है?

हजारों साल पहले भारत में लिखे गए सबसे प्रमुख उपनिषद् 'इशोपनिषद्' की शुरुआत में ही तत्त्वद्रष्टा गुरु ने अपने शिष्यों से परिवर्तनशील जगत के बारे में कहा:

‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मागृधः कस्यस्विद्धनम्।

यानि संसार में रहते हुए उसका त्याग पूर्वक भोग करो, और किसी दूसरे की सम्पत्ति का लालच मत करो। ढाई हजार साल पहले भगवान् बुद्ध ने अपरिग्रह यानि आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल को अपने सिद्धांतों में प्रमुख स्थान दिया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का trusteeship का सिद्धांत भी आवश्यकता यानि need के अनुसार उपयोग और उपभोग करने के पक्ष में था; greed पर आधारित शोषण का उन्होंने सीधा विरोध किया था। सोचने का विषय है कि त्यागपूर्वक भोग से आवश्यकतानुसार उपयोग करते हुए अब हम लालच के वश प्रकृति के शोषणतक कैसे पहुँच गए? यह हमारा विकास हुआ है या पतन? हमारे दिमाग की येदुरावस्था, हमारे स्वार्थ की खौफनाक झलक, हमें क्यों आत्म-चिंतन पर मजबूर नहीं करती?

अगर हम सोचें तो पाएंगे कि आज पर्यावरण में व्याप्त भयंकर कुपरिणामों के इलाज का एक अचूक नुस्खा है – प्राचीन भारतीय दर्शन का मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य। यही नहीं, इस दर्शन से जन्मी योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय परम्पराओं की समग्र पद्धति न सिर्फ परिवेश और हमारे बीच के fracture को heal कर सकती है, बल्कि हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और संतुलन भी प्रदान करती है। वातावरण को बचाने और climate change का प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा लक्ष्य मेरी सरकार ने देश के सामने रखा है। सन् 2022 तक हमें भारत में 175 GW renewable energy का उत्पादन करना है। पिछले करीब तीन वर्षों में 60 GW, यानि इस लक्ष्य का एक तिहाई से भी अधिक हम प्राप्त कर चुके हैं।

2016 में भारत और फ्रांस ने मिलकर एक नये अंतर्राष्ट्रीय treaty based organization की कल्पना की। यह क्रांतिकारी कदम अब एक सफल प्रयोग में बदल गया है। International Solar Alliance के रूप में यह पहल आवश्यक Treaty ratification के बाद अब एक वास्तविकता है। मुझे बेहद खुशी है कि इस वर्ष मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और मेरे संयुक्त निमंत्रण पर इस Alliance के सदस्य देशों के leaders नई दिल्ली में होने वाले Alliance के पहले summit में भाग लेंगे।

Friends,

दूसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद। इस संबंध में भारत की चिंताओं और विश्वभर में पूरी मानवता के लिए इस गम्भीर खतरे के बढ़ते और बदलते हुए स्वरूप से आप भली-भांति परिचित हैं। मैं यहाँ सिर्फ दो आयामों पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक है good terrorist और bad terrorist के बीच बनाया गया artificial भेद। दूसरा समकालीन गंभीर पहलू जिसपर मैं आपका ध्यान चाहता हूँ वह है पढ़े-लिखे और सम्पन्न युवाओं का radicalise होकर आतंकवाद में लिप्त होना। मुझे आशा है कि इस फोरम में आतंकवाद और हिंसा की दरारों से, इनके द्वारा उत्पन्न fracture से हमारे सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर और उनके समाधान के विषय पर चर्चा होगी।

Friends,

तीसरी चुनौती मैं यह देखता हूँ कि बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि Globalization अपने नाम के विपरीत सिकुड़ रहा है। इस प्रकार की मनोवृत्तियों और गलत प्राथमिकताओं के दुष्परिणाम को climate change या आतंकवाद के खतरे से कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि हर कोई interconnected विश्व की बात करता है लेकिन globalization की चमक कम हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्श अभी भी सर्वमान्य हैं। World Trade Organization भी व्यापक है। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने हुए विश्व संगठनों की संरचना, व्यवस्था और उनकी कार्य पद्धति क्या आज के मानव की आकांक्षाओं और उसके सपनों को, आज की वास्तविकता को परिलक्षित करते हैं?

इन संस्थानों की पुरानी व्यवस्था और आज के विश्व में खासतौर पर बहुतायत विकासमान देशों की आवश्यकताओं के बीच एक बड़ी खाई है। Globalization के विपरीत protectionism की ताकतें सर उठा रही हैं। उनकी मंशा है कि न सिर्फ वे खुद globalization से बचें बल्कि globalization के प्राकृतिक प्रवाह का रुख भी पलट दें। इसका एक परिणाम यह है कि नये-नये प्रकार के tariff और non-tariff barrier देखने को मिलते हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते और negotiations रुक-से गये हैं। Cross-border वित्तीय निवेश में ज्यादातर देशों में कमी आई है। और Global supply chains की वृद्धि भी रुक गयी है। Globalisation के विरुद्ध इस चिंताजनक स्थिति का हल अलगाव में नहीं है। इसका समाधान परिवर्तन को समझने और उसे स्वीकारने में है, बदलते हुए समय के साथ चुस्त और लचीली नीतियां बनाने में है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की दीवारें और खिड़कियां सभी तरफ से बंद हो। मैं चाहता हूँ की सभी देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर में पूरी स्वच्छता से आ जा सके। लेकिन इस हवा से मेरे पैर उखड़ जायें, यह मुझे मंजूर नहीं होगा। "आज का भारत महात्मा गांधी के इसी दर्शन और चिंतन को अपनाते हुए पूरे आत्मविश्वास और निर्भिकता के साथ विश्व भर से जीवनदायिनी तरंगों का स्वागत कर रहा है।

Friends, भारत का लोकतंत्र देश की स्थिरता, निश्चितता और सतत विकास का मूल आधार है। धर्म, संस्कृति, भाषा, वेश-भूषा और खान-पान की अपार विविधता से भरे-पूरे भारत के लिए लोकतंत्र महज़ एक राजनैतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीवन शैली है। हम भारतीय यह भली-भांति जानते और समझते हैं की विविधता की अनेकता को सौहार्द, सहयोग और संकल्प की एकता में बदलने के लिए लोकतांत्रिक परिवेश और स्वतंत्रताओं का महत्व क्या है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ हमारी विविधता का ही पालन-पोषण नहीं करता, बल्कि सवा सौ करोड़ से भी अधिक भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक परिवेश, road map और template भी प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक मूल्य और समावेशी आर्थिक विकास और प्रगति में तमाम दरारों को पाटने की संजीवनी शक्ति है। भारत के साठ करोड़ मतदाताओं ने 2014 में तीस साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक Party को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। हमने किसी एक वर्ग या कुछ लोगों के सीमित विकास का नहीं बल्कि सबके विकास का संकल्प किया। मेरी सरकार का मोटो है: "सबका साथ -सबका विकास"। प्रगति के लिए हमारा vision समावेशी है, हमारा mission समावेशी है। यह समावेशी दर्शन मेरी सरकार की हर नीति का हर योजना का आधार है। चाहे वह करोड़ों लोगों के लिए पहली बार bank खाते खुला के financial inclusion करना हो, या गरीबों तक, हर जरूरतमंद तक digital technology द्वारा direct benefit transfer. या फिर gender justice के लिए 'बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ'।

हम मानते हैं कि प्रगति तभी प्रगति है, विकास तभी सच्चे अर्थों में विकास है जब सब साथ चल सकें। हम अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में केवल छोटे-मोटे सुधार ही नहीं कर रहे, बल्कि आमूलचूल रूपान्तरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है वो है reform, perform and transform. आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में निवेश करना, भारत की यात्रा करना, भारत में काम करना, भारत में manufacture करना, और भारत से अपने products and services को दुनिया भर को export करना, सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। हमने लाइसेंस-परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। Red tape हटा कर हम red carpet बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र foreign direct investment के लिए खुल गए हैं। 90 प्रतिशत से अधिक में automatic route से निवेश सम्भव है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिल कर सैकड़ों reforms किये हैं। 1400 से अधिक ऐसे पुराने कानून, जो business में, प्रशासन में, और आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन में अडचने डाल रहे थे, ऐसे पुराने कानूनों को हमने खत्म कर दिया है।

70 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश में एक एकीकृत कर व्यवस्था goods and service tax – GST - के रूप में लागू कर ली गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम technology का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को transform करने के लिए हमारे संकल्प और हमारे प्रयासों का विश्व भर की business community ने स्वागत किया है। भारत में democracy, demography और dynamism मिल कर development को साकार कर रहे हैं, destiny को आकार दे रहे हैं। दशकों के नियंत्रण ने भारत के लोगों की, भारत के युवा की क्षमताओं को जकड़ रखा था। लेकिन

अब, हमारी सरकार के निर्भीक नीतिगत फैसलों ने, असरदार कदमों ने परिस्थितियां बदल दी हैं। लगभग साढ़ेतीन साल के कम समय में जो दूरगामी और बड़े परिवर्तन भारत में हुए हैं और हो रहे हैं वे सवा सौ करोड़ भारतियों की अपेक्षाओं, उनके पुरुषार्थ और उनकी परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता का यशोगान है। अब भारत के लोग, भारत के युवा 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान के लिए समर्थ हैं।

यही नहीं, जब Innovation और Entrepreneurship (आंत्रप्रेनयूरशिप) के ज़रिये वे जॉब-सीकर नहीं, जॉब गिवर बनेंगे तो उनके लिए, उनके देश के लिए और आप के व्यवसाय के लिए कितने रास्ते खुलेंगे इसकी कल्पना ही की जा सकती है। आप सभी विश्व के प्रमुख लीडर्स हैं, और विश्व में हो रहे परिवर्तनों से, भारत की ranking और rating में हुए सुधार से, और आगे के लिए जो रास्ता हमने चुना है - इन सबसे आप भली भाँति परिचित हैं। लेकिन इन सभी आंकड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत के लोगों ने हमारी नीतियों का, अपनी भविष्य में बदलाव के लिए हुई नई पहलों और अच्छे भविष्य के सुनहरे संकेतों का स्वागत किया है। स्वेच्छा से subsidy का त्याग, या फिर चुनाव दर चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से हमारी नीतियों और सुधारों में अपना विश्वास व्यक्त करना हो- ऐसे अनेक प्रमाण भारत में इन अभूतपूर्व परिवर्तनों के व्यापक समर्थन की पुष्टि करते हैं।

Friends,

विश्व में तमाम तरह के फ्रैक्चर और तमाम तरह की दरारों को देखते हुए, यह आवश्यक है कि हमारे साझा भविष्य के लिए हम कई दिशाओं पर ध्यान दें। सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग के संबंध हों। यह आवश्यक है कि विश्व के प्रमुख देशों के बीच प्रतिस्पर्धा उनके बीच एक दीवार बनकर न खड़ी हो जाए। साझा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने मतभेदों को दरकिनार करके एक larger vision के तहत साथ मिल कर काम करना होगा। दूसरी आवश्यकता है कि नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। खास तौर पर जब हम ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जहाँ हमारे चारों ओर होने वाले बदलाव अनिश्चितताओं को जन्म दे सकते हैं, तब अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का सही spirit में पालन ज़रूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के प्रमुख राजनैतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा से संबंधित संस्थानों में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उनमें सहभागिता और लोकतांत्रिकरण को आज की परिस्थिति के अनुरूप बढ़ावा दिया जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें विश्व की आर्थिक प्रगति में और तेज़ी लानी होगी। इस बारे में विश्व में आर्थिक वृद्धि के लिए हाल के संकेत उत्साहजनक हैं। Technology और digital revolution ऐसे नए समाधानों की संभावना बढ़ाते हैं जिनसे हम गरीबी और बेरोज़गारी जैसी पुरानी समस्याओं और चुनौतियों का नए सिरे से मुकाबला कर सकते हैं।

Friends,

इस प्रकार के प्रयासों में भारत ने हमेशा सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है। आज से ही नहीं, अपनी स्वतंत्रता के समय से नहीं, बल्कि पुरातन काल से भारत चुनौतियों का मुकाबला करने में सबके साथ सहयोग का हामी रहा है। पिछली शताब्दी में जब विश्व दो विश्व युद्धों के संकट से गुज़रा तब अपना कोई निजी स्वार्थ न होते हुए भी, कोई आर्थिक या territorial हित न होते हुए भी भारत शान्ति और मानवता के उच्च आदर्शों की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ। डेढ़ लाख से भी अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी। ये वही आदर्श हैं जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से भारत ने UN peace keeping ऑपरेशंस में सैनिकों का सबसे बड़ी संख्या में योगदान किया है। ये वही आदर्श हैं जिनकी प्रेरणा और शक्ति हमें संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने पड़ोसियों मित्र देशों और मानव मात्र की सहायता करने के लिए उत्साहित करती है। चाहे नेपाल में भूकंप हो, या हमारे दूसरे पड़ोसी या मित्र देशों में बाढ़, तूफ़ान, या दूसरी प्राकृतिक आपदाएँ। भारत ने First Responder के रूप में सहायता पहुँचाना अपना सबसे प्रमुख कर्तव्य समझता है। यमन में जब हिंसा की लपटों ने भारत ही नहीं दुनिया के बहुत से देशों के नागरिकों को चपेट लेना शुरू किया तो हमने अपने संसाधनों के ज़रिए भारतीयों को ही नहीं, अन्य देशों के लगभग 2 हज़ार नागरिकों को भी वहाँ से सुरक्षित निकाला। स्वयं एक विकासशील देश होने के बावजूद भारत development cooperation में, capacity building में, आगे बढ़कर सहयोग करता आ रहा है। Africa के देश हों, या भारत के पड़ोसी, या South East Asia के देश हों, या फिर Pacific Islands हों, सभी के साथ हमारे सहयोग की रूपरेखा और हमारे projects उन देशों की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों पर आधारित होते हैं।

Friends,

भारत ने कोई राजनैतिक या भौगोलिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी है। हम किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं करते बल्कि उस देश के लिए उसके साथ मिलकर उनका विकास करते हैं। भारतीय भूभाग में हज़ारों साल से विविधता के सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का सीधा नतीजा यह है कि हम multi-cultural संसार में और multi-polar विश्व-व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र, विविधता का सम्मान, सौहार्द और समन्वय, सहयोग और संवाद से सभी विवादों और दरारों को मिटाया जा सकता है। शान्ति, स्थिरता और विकास के लिए यह भारत का जांचा-परखा नुस्खा है। यही नहीं, a predictable, stable, transparent and progressive India will continue to be the good news in an otherwise state of uncertainty and flux. An India where enormous diversity exists harmoniously (हमोनिअसली) will always be a unifying and harmonising force. अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए ही नहीं भारतीय मानस ने, भारत के चिंतकों ने ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माकश्चिद् दुःख भाग भवेत् - यानी सब प्रसन्न हों, सब स्वस्थ हों, सबका कल्याण हों और किसी को दुःख ना मिले - यह सपना देखा है। और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए, इस सपने को साकार करने के लिए रास्ता भी दिखाया है:

सहनाऽवतु, सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे।

तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहे।

इस हज़ारोंसाल पुरानी भारतीय प्रार्थना का अभिप्राय है कि हम सब मिलकर काम करें, मिलकर चलें, हमारी प्रतिभाएं साथ-साथ खिलें और हमारे बीच कभी भी द्वेष न हो। पिछली शताब्दी के महान भारतीय कवि और Nobel पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे heaven of freedom की कल्पना की "where the World has not been broken up into fragments by narrow domestic walls". आइए हम मिलकर एक ऐसा heaven

of freedom बनाएँ जहाँ सहयोग और समन्वय हो, divide और fracture नहीं। आइए हम सब साथ-साथ दुनिया को उसकी दरारों और अनावश्यक दीवारों से मुक्ति दिलाएँ।

Friends,

भारत और भारतीयों ने पूरे विश्व को एक परिवार माना है। विभिन्न देशों में भारतीय मूल के 30 million लोग रह रहे हैं। जब हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है, तो दुनिया के लिए भी हम भारतीय उनका परिवार हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि अगर आप वेल्थ के साथ वैलनेस चाहते हैं, तो भारत में काम करें। अगर आप health के साथ जीवन की wholeness यानि समग्रता चाहते हैं तो भारत में आयें। अगर आप prosperity के साथ peace चाहते हैं तो भारत में रहें। आप भारत आएँ, भारत में हमेशा आपका स्वागत होगा। मुझे आप सब से बातचीत करने का यह बहुमूल्य अवसर प्रदान करने के लिए, World Economic Forum का, श्री क्लास श्वाब का और आप सबका मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

एकेटी/एसएच/बीएम/एसबीपी

(रिलीज़ आईडी: 1517524) आगंतुक पटल : 1655

प्रधानमंत्री कार्यालय

मुद्रा योजना लाभार्थियों के साथ संवाद के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 29 MAY 2018 2:17PM by PIB Delhi

भाइयों और बहनो,

मेरा यह सौभाग्य है कि जो योजना मेरे हृदय के बेहद करीब है उस योजना के कर्मयोगियों से, उद्यमशील युवाओं से, परंपरा के बाहर निकली बहनो से बातचीत करने का आज मुझे अवसर मिला है। आप वे लोग हैं जो बैंधे - बैंधाए रास्तों पर चलने के बजाय खुद के रास्ते खुद तय करते हैं, अपने साहस और इच्छाशक्ति से रास्ते तैयार करते हैं। देश की समृद्धि और समाज की खुशहाली में आप सब का बहुत बड़ा योगदान है।

आज मेरे साथ-साथ पूरा देश आप सब के इस साहस का, इस निर्णय का, इस initiative का, आपकी इस यात्रा के संस्मरण सुनने के लिए इस विडीओ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब के साथ जुड़ा हुआ है। अभी पिछले महीने ही प्रधानमंत्री आवास पर मुझे मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। उनके अनुभव, उनका संघर्ष, उनकी तरक्की की कहानीयाँ संतोष भी देती हैं और मन को गर्व से प्रफुल्लित भी करती हैं। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि कभी-कभी मौका अगर पढ़ जाये तो देश भर के मुद्रा के लाभार्थियों से बात करने का अवसर मैं दूँगा देश भर के मुद्रा के लाभार्थियों से बातचीत करूँगा, गप्पें, गोष्ठी करूँगा। और आज Technology के माध्यम से आपका भी समय बच गया, मेरा भी समय बच गया, फिर भी हमारे बीच वही बंधन बंध गया, वही प्यार भरा रिश्ता जुड़ गया। आपके अनुभव आपकी भावनाएँ सीधे-सीधे मुझे सुनने को मिल रही हैं, बीच में किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं।

देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में आप जैसे उद्यमियों का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन पहले उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके बारे में कभी नहीं सोचा गया। आपको मालूम है आज से 25-30 साल पहले political benefit के लिए लोन मेलें चलते थे और जो राजनितिक उसूल रखने वाले लोग थे उनके चले-चपाटे, ठेकेदार, वोट बैंक की राजनीति, ये बैंकों से रुपये ले जाते थे। खबरें भी बहुत छपती थी कितना बैंक लोन दिया गया। बाद में क्या हुआ किसी ने पूछा ही नहीं। हमने न लोन मेलें किये न बिचौलियों को जगह दी। हमने देश के नौजवान, देश की माताएं-बहनें जो खुद के इनिशिएटिव से कुछ करना चाहती हैं, खुद बैंक के दफ्तर में जा कर बात करना चाहती हैं, आप अपनी बात रख सकती हैं, मुद्रा योजना एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो इच्छा रखने वाले, कुछ करने का इरादा रखने वाले देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हमने हमारे छोटे उद्यमियों पर भरोसा किया, उनके business skills पर भरोसा किया। मुद्रा योजना के तहत उन्हें loan दिया गया ताकि वे अपना business खोल सकें, उसका विस्तार कर सकें। मुद्रा योजना से न केवल स्व-रोजगार के अवसर बल्कि आज यह जॉब मल्टीप्लायर का भी काम कर रही है।

आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में लाइसेंस राज की एक बड़ी बीमारी देखी गई है। लोन उसको मिलता था, जिसकी पहचान होती थी; काम उसी का होता था जिसका नाम होता था। कहीं न कहीं इस प्रथा ने गरीब को सिस्टम से बाहर ही खड़े रखा क्योंकि न उसके पास बड़ा नाम था और न ही कोई अप्रोच। यह एक बड़ा कारण था कि हजारों-लाखों छोटे उद्यमी इतने वर्षों से अपनी काबिलियत के हिसाब से या तो अपना व्यापार ही नहीं शुरू कर पाते थे या फिर उसका विस्तार नहीं कर पाते थे। आर्थिक मदद के लिए साहूकारों के चंगुल में ही फंसे कर रह जाते थे।

इस देश में एक ऐसा समय था जब खुद वित्त मंत्री फोन कर के बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवाते थे और दूसरी तरफ एक छोटा उद्यमी साहूकारों को 30-40 प्रतिशत ब्याज देने के चक्कर में कुछ ऐसे फंस जाता था कि वह पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाता था। इस vicious cycle को कभी तो टूटना था, किसी को तो इसे तोड़ना ही था, हमने इस दिशा में प्रयास किया और हम इसमें सफल रहे हैं। इस vicious cycle को हम तोड़ रहे हैं...

भरोसे की, विश्वास की ताकत से। सरकार का गरीब पर विश्वास, गरीब के सपनों पर विश्वास, गरीब की मेहनत पर विश्वास।

अगर युवाओं को दशकों पहले मुद्रा जैसी योजना मिल जाती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि शहरों की और पलायन की समस्या भी इतनी विकराल नहीं होती। बिना बैंक गारंटी कर्ज मिलने पर, कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलने पर युवा अपने गांव या शहर में रहते हुए ही अपने दम पर रोजगार करते। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना किसी collateral के मुद्रा लोन मिल रहा है। आज एक सामान्य जन भी, बिना किसी खास नाम और पहचान वाला व्यक्ति भी मुद्रा लोन की मदद से उद्यमी बन सकता है। और आज इसकी भी जरूरत नहीं है कि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार सरकार में ही हो। आज देश में हुनर की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, उसके पास कोई न कोई विशेष हुनर है। जरूरत है, उस हुनर को पहचान देने की, उसे प्रोत्साहन देने की। मुद्रा योजना से लोगों, खासकर हमारे युवाओं के इसी हुनर को बल मिल रहा है।

जब हुनर को प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे हुनर और खिलता है, जीवन में बदलाव आता है। मान लीजिए, किसी के पास कपड़ों में कढ़ाई करने का हुनर था, उसने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर कपड़ों में कढ़ाई करने का बिजनेस शुरू किया। धीरे-धीरे वह डिजाइनर कपड़ों का काम करने लगेगा। किसी को अपना हैंडलूम का बिजनेस शुरू करने में मदद मिली। मुद्रा योजना ने एक तरह से देश के सामान्य व्यक्ति के हुनर को निखारने का काम किया है, उस हुनर को पहचान दिलाने और लोगों को सशक्त बनाने का काम किया है। मुद्रा योजना के तहत लाभ मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 12 करोड़ लोन के माध्यम से पौने 6 लाख करोड़ की राशि दी गई है।

कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास योजनाओं के लिए फंड होता है लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुद्रा एक ऐसी योजना है जिसमें लक्ष्य से अधिक लोन दिए गए हैं। इसमें भी 28 प्रतिशत यानि सवा तीन करोड़ से ज्यादा ऋण ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है। ये वो लोग हैं जो एक तरह से बेरोजगारी से निकलकर रोजगार पैदा करने की स्थिति में आए। सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें 74 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं यानि 9 करोड़ से ज्यादा लोन सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं। जब महिला आगे बढ़ती है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनती है तो पूरे परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है, सोच ही बदल जाती है, समाज सशक्त होता है। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत 55 प्रतिशत लोन पिछड़े समाज के व्यक्तियों को दिए गए हैं यानि कुल 12 करोड़ loans में से 55 प्रतिशत loan SC/ST और OBC समाज के उद्यमियों को दिए गए हैं। दशकों से हम गरीबी के नाम पर नारे सुनते आए हैं, गरीबों के उत्थान की बातें सुनी हैं लेकिन मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जो बिना किसी भेदभाव के पिछड़े समाज को आर्थिक एवं सामाजिक बल देने का, उन्हें सशक्त करने का काम कर रही है।

जो कारवां बैंकों के साथ शुरू हुआ था, उसमें धीरे-धीरे आज अनेकों संस्थान जुड़ते चले गए हैं। आज सिर्फ 110 बैंक ही नहीं, इनके अलावा 72 Micro financial Institutions (MFI) और 9 Non-Banking Financial Companies (NBFCs) भी मुद्रा लोन दे रहे हैं। बैंकों ने भी मुद्रा लोन लेने की प्रक्रिया को और आसान बनाने का काम भी किया है। Documents जुटाना तनाव ना बने, इसलिए कागजी प्रक्रिया को भी सरल रखा गया। Self Employed होना आज एक गर्व की बात है और इसके प्रेरणास्त्रोत आप सब लोग हैं।

अतुल कुमार तिवारी/वंदना जाटव/सतीश शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1533742) आगंतुक पटल : 657

प्रधानमंत्री कार्यालय

वाणिज्य भवन के शिलान्यास पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 22 JUN 2018 4:12PM by PIB Delhi

मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी, आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्री सी. आर. चौधरी जी, वाणिज्य मंत्रालय और संबंधित विभागों के अधिकारीगण और यहां उपस्थित अन्य महानुभाव

सबसे पहले मैं आप सभी को वाणिज्य भवन का शिलान्यास होने पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आज इसका कार्य शुरू हो गया है और जैसा कि मंच पर ही बताया गया है कि अगले वर्ष दिसंबर तक निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समय की सीमाओं में ही वाणिज्य भवन बनेगा और जल्द से जल्द इसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा।

साथियों, समय की बात सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस सरकार के दौरान जितने भी भवनों का शिलान्यास या उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला, उसमें ज्यादातर में एक बात कॉमन थी। कॉमन ये की इमारतों का निर्माण भी सरकारों के काम करने के तरीकों का प्रतिबिम्ब होता है। न्यू इंडिया की ओर बढ़ते देश और पुरानी व्यवस्थाओं के बीच का फर्क भी इसी से पता चलता है।

साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे याद है जब वर्ष 2016 में प्रवासी भारतीय केंद्र का लोकार्पण हुआ, तो उस समय ये बात भी सामने आई थी कि उस केंद्र का ऐलान अटल बिहारी वाजपायी जी के समय हुआ था। बाद में उसे मूर्त रूप में आते-आते 12 साल लग गए।

पिछले साल दिसंबर में जिस डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण हुआ, उसे बनाने का निर्णय भी 1992 में लिया गया था। लेकिन इसका शिलान्यास हुआ वर्ष 2015 में मैंने कहा, कहाँ 1992 कहाँ 2015, इसका लोकार्पण 2017 में हुआ। यानि निर्णय होने के बाद 23-24 साल लग गए, सिर्फ एक सेंटर बनने में।

साथियों, इसी साल मार्च में मैंने Central Information Commission के नए भवन को भी देश को समर्पित किया था। CIC के लिए नए भवन की मांग भी 12 साल से हो रही थी लेकिन इसके लिए भी काम NDA की अभी की सरकार ने ही शुरू करवाया और तय समय में उसे पूरा भी किया।

एक और उदाहरण है अलीपुर रोड में बनी आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का। दो महीना पहले इसका भी लोकार्पण किया गया है। इस स्मारक के लिए भी बरसों तक चर्चा हुई, अटल जी के समय काम में तेजी भी आई, लेकिन बाद में दस बारह साल सब ठप पड़ गया।

दिल्ली की ये चार अलग-अलग इमारतें, प्रतीक हैं कि जब सरकार silos में काम नहीं होता, जब सारे विभाग, मंत्रालय, silos से निकलकर solution के लिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो कितना अच्छा और कितना जल्दी परिणाम निकलता है। हर काम को अटकाने-भटकाने-लटकाने की प्रवृत्ति से देश अब आगे निकल चुका है।

मुझे खुशी है कि आज इसमें पाँचवाँ प्रतीक जुड़ने की शुरुआत हो गई है। इस वाणिज्य भवन में, एक छत के नीचे, commerce sector के हर क्षेत्र से silos को खत्म करने का कार्य और बेहतर तरीके से किया जाएगा, मेरी यही कामना है। मुझे विश्वास है की यह परिपूर्ण भी होगा।

साथियों, आज भारत समय के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हमारा Demographic Dividend किसी भी देश के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। हमारी democracy को हमारे नौजवान नई ऊर्जा देते हैं। ये नौजवान 21वीं सदी के भारत का आधार हैं। उनकी आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति, सिर्फ कुछ मंत्रालयों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

भारत पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने से चूक गया था। तब उसकी अनेक वजहें थीं। लेकिन अब उतनी ही वजहें हैं जिनकी वजह से भारत अब इस शताब्दी की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक बन सकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे 4th Industrial Revolution भी कहते हैं, उसका मुख्य आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है और निश्चित तौर पर भारत इसमें दुनिया के कई देशों से कहीं आगे है।

आज आप वाणिज्य मंत्रालयों के भी जितने लक्ष्यों को देखेंगे, जितने भी कार्यों को देखेंगे, तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी की प्रमुखता ही आपको नजर आएगी।

ये वाणिज्य भवन ही देखिए। जिस जमीन पर ये इमारत बनेगी, वो पहले Directorate General of Supplies and Disposal के अधिकार में थी। सौ वर्ष से भी ज्यादा पुराना ये विभाग अब बंद हो चुका है और इसकी जगह ली है डिजिटल तकनीक पर आधारित Government-e-Marketplace- GeM ने। सरकार किस तरह से अपनी जरूरत के सामान की खरीद करती है, उस व्यवस्था को GeM ने पूरी तरह से बदल दिया है।

आज की तारीख में 1 लाख 17 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े विक्रेता, कंपनियां इससे जुड़ी चुकी हैं। इन Sellers को 5 लाख से ज्यादा Orders GeM के माध्यम से दिए जा चुके हैं। बहुत कम समय में GeM पर 8700 करोड़ रुपये के सामान को खरीदा गया है।

जिस तरह GeM ने देश के सुदूर कोने में बैठे छोटे-छोटे उद्यमियों को अपने Products सीधे सरकार को बेचने का अवसर मुहैया कराया है, उसके लिए Commerce Ministry प्रशंसा की पात्र है। लेकिन आप लोगों के लिए, मैं इसे एक लंबी यात्रा की शुरुआत मानता हूँ।

GeM का विस्तार और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये देश के MSME सेक्टर, छोटे उद्यमियों को International Commerce की तरफ ले जाए, इस बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज देश में 40 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती हुई संख्या, सस्ता डेटा, आपके कार्यों को और आसान कर रहा है।

साथियों, हमारे यहां कहा गया है- को हि भारः समर्थानाम् किम् दूर व्यवसायिनाम्। यानि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, उसके लिए कोई चीज भारी नहीं होती। इसी तरह व्यवसायियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती। आज टेक्नोलॉजी ने व्यापार को इतना सुगम बना दिया है कि दूरी दिनोंदिन कम होती जा रही है। ये टेक्नोलॉजी देश के बिजनेस कल्चर में जितनी बढ़ेगी, उतना ही फायदा पहुंचाएगी।

हम देख रहे हैं कि किस तरह एक वर्ष से भी कम समय ने GST देश में बिजनेस का तरीका बदल दिया है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या ये संभव होता? नहीं। आज GST की वजह से ही देश में Indirect Tax और उससे जुड़ने वाले लोगों का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है।

स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में Indirect Tax सिस्टम से जहां सिर्फ 60 लाख जुड़े हुए थे, वहीं GST के बाद के 11 महीनों में ही अब तक 54 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है और इनमें से 47 लाख से ज्यादा रजिस्टर हो चुके हैं। इस तरह रजिस्टर्ड लोगों की संख्या अब एक करोड़ से ज्यादा हो चुकी है।

ये इस बात को दर्शाता है कि प्रक्रियाओं को सरल करने पर, Minimum Government, Maximum Governance की राह पर चलने पर नतीजे भी आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाते हैं।

साथियों, आप भली-भांति जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने People friendly, Development friendly और Investment friendly माहौल बनाने का निरंतर प्रयास किया है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के Macro-Economic Indicators stable बने हुए हैं। Inflation हो, Fiscal Deficit हो, या फिर Current Account Balance, इनमें पहले की सरकारों की तुलना में सुधार हुआ है।

भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी पिछले ही क्वार्टर में देश की विकास दर ने 7.7 प्रतिशत के आंकड़े को Touch किया है। पिछले 4 वर्षों में हुआ विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा का भंडार अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

आज भारत FDI Confidence Index में top two emerging market performers में से एक है। Ease of doing Business की रैंकिंग में 142 से 100 नंबर पर पहुंचना, Logistics Performance Index में 19 अंकों का सुधार, Global Competitiveness Index में रैंकिंग 71 से सुधकर 39 पर पहुंचना, Global Innovation Index में 21 अंक का उछाल आना, ये इसी विजन का नतीजा है।

आपकी जानकारी में अवश्य होगा कि हाल ही में भारत ने दुनिया के top 5 Fin Tech countries में भी जगह बना ली है।

लेकिन इन Positive Indicators के साथ ही आगे बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अब आगे क्या? साथियों, सात प्रतिशत, आठ प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना है। दुनिया की नजरें आज भारत को इस दृष्टि से भी देख रही हैं कि भारत कितने वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर के क्लब में शामिल होता है?

मैं मानता हूं कि Commerce Ministry को, आप सभी जिम्मेदार अधिकारीगणों को इन लक्ष्यों को एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर की गई ये प्रगति सीधे-सीधे देश के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई है।

इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जब भी मैं Ease of Trading, Ease of Doing Business की बात करता हूं, वो साथ ही Ease of Living का विषय भी हमेशा उठाता हूं। आज की Interconnected दुनिया में ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

जब बिजली कनेक्शन लेना आसान होता है, कंस्ट्रक्शन को लेकर मंजूरी जल्दी मिलती है, जब उद्योगों को, कंपनियों को प्रक्रियाओं से उलझना नहीं होता, तो इसका लाभ जन सामान्य तक भी पहुंचता है। इसलिए आप लोगों के लिए भी ये एक चैलेंज है कि अब भी जो अलग-अलग सेक्टरों में जो bottleneck बचे हुए हैं, जहां पर silos में काम हो रहा है, उन्हें जितना जल्दी हो सके दूर किया जाए।

विशेषकर Infrasector में जो दिक्कतें आती हैं, high Transaction cost होता है, Manufacturing को बढ़ाने में जो बातें गतिरोध पैदा करती हैं, services का inadequate diversification करती हैं, उन्हें रोका जाना, सुधारा जाना बहुत आवश्यक है।

मुझे खुशी है कि अभी हाल ही में Department of Commerce ने देश के logistics sector के integrated development का बीड़ा उठाया है। ये initiative देश में trade के environment को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।

साथियों, Integrated logistics action plan आज समय की मांग है और New India की जरूरत भी है। Policy में बदलाव करके, जो वर्तमान में Procedures हैं, उन्हें सुधार करके, आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

मुझे बताया गया है कि Department of Commerce इस दिशा में एक Online Portal पर भी काम कर रहा है। Global Trade में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए, नई ऊँचाई पर पहुंचाने के लिए सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों का एकसाथ मिलकर काम करना भी आवश्यक है। जिसको हम कहते हैं, 'Whole of Government' Approach, उसे अपनाए जाने की जरूरत है।

ये भी एक अच्छा कदम है कि Council for Trade Development and Promotion राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में International Trade को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है। भारत के Exports को बढ़ाना है तो राज्यों को Active Partner बनाकर ही आगे बढ़ना होगा।

मैं समझता हूँ कि राज्यों में State level export strategy का निर्माण करके, उन्हें National Trade Policy के साथ तालमेल करते हुए, आर्थिक सहायता करते हुए, जितने भी stakeholders हैं, उन्हें साथ लेते हुए, इस दिशा में जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, उतना ही देश का लाभ होगा।

साथियों, International मार्केट में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जो हमारे Traditional Products और Markets हैं, उन्हें बनाए रखते हुए नए Products और नए Markets पर ध्यान दिया जाना भी बहुत आवश्यक है। हमें देश के भीतर की चुनौतियों के साथ ही देश के बाहर की परिस्थितियों के लिए भी खुद को और मजबूत करना होगा।

जब हम short-term developmental gains और long-term sustainability के बीच एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो उसके नतीजे भी दिखाई देंगे।

पिछले साल दिसंबर में Foreign Trade policy से जुड़ा जो Mid Term review किया गया था, उसे भी मैं बहुत सकारात्मक पहल मानता हूँ। Incentive बढ़ाकर, MSME सेक्टर की Hand Holding करके निर्यात को बढ़ाने के लिए किया गया हर बदलाव प्रशंसनीय है। ये सीधे-सीधे देश की रोजगार जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है।

एक और महत्वपूर्ण विषय है-Product की Quality. यही वजह है कि साल 2014 में मैंने 15 अगस्त को लाल किले से Zero Defect, Zero Effect का आह्वान किया था। उद्योग छोटा हो या बड़ा, हर मैन्यूफैक्चरर को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो ऐसे Products बनाए, जिसमें Zero Defect हो, कोई हमारे exported goods को वापस न भेजे। इसके साथ ही मैंने Zero Effect की बात की थी, यानी हमारे Products पर्यावरण पर कोई negative effect न डालें।

Products की Quality को लेकर ये जागरूकता Make in India की चमक बढ़ाने और New India की पहचान को मजबूत करने का काम करेगी।

आप भी जब देखते होंगे कि जहां 2014 में हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां थीं, वो अब बढ़कर 120 हो गई हैं, बहुत ही कम कीमत पर विश्व स्तर के Quality Product का निर्माण कर रही हैं, तो खुद को गौरवांवि्त महसूस करते होंगे।

साथियों, ये समय संकल्प का है, चुनौतियां स्वीकारने का है।

क्या Department of Commerce ये संकल्प ले सकता है की विश्व के कुल निर्यात में भारत के योगदान को बढ़ाकर दोगुना करे, अभी के 1.6 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 3.4 प्रतिशत तक ले जाए। ये world economy में GDP के भारत के योगदान के बराबर होगा। इस से देश में रोज़गार के और नए अवसर बनेंगे और हमारी per capita इनकम में भी बढ़ोतरी होगी।

इसके लिए सरकार के सभी विभागों और यहाँ उपस्थित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा।

इसके अलावा एक और संकल्प लिया जा सकता है इम्पोर्ट को लेकर। क्या हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं? चाहेवो एनर्जी इम्पोर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पोर्ट हो, डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग का क्षेत्र हो या मेडिकल devices का क्षेत्र हो। Make in india के द्वारा ये संभव है।

डोमेस्टिकमैन्यूफैक्चरिंग के द्वारा इम्पोर्ट में 10% की कमी देश में साढ़े तीन लाख करोड़रुपए की आय बढ़ा सकती है। ये देश की GDP में वृद्धि को डबल डिजिट में ले जाने में एक Effective tool बन सकती है।

मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्यूफैक्चरिंग का ही उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या ये आप सभी लोगों के लिए एक चुनौती नहीं है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कुल मांग का 65 प्रतिशत हमें बाहर से खरीदना पड़ता है?

जैसा मोबाइल फोन के क्षेत्र में हुआ है, वैसे हीक्या आप इस चुनौती को स्वीकार कर, देश को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बना सकते हैं?

साथियों, आप इससे भी परिचित हैं कि इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम पिछले वर्ष उठाया गया है। Public Procurement (Preference to Make in India)आदेश के द्वारा सरकार के तमाम विभागों और संस्थानों में खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के Domestic Source से खरीदने पर बल दिया जा रहा है। इस आदेश को पूरी गंभीरता के साथ लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इसके लिए आप सभी लोगों को, सरकार के सभी निकायों को, अपनी मॉनीटरिंग व्यवस्था को, इस आदेश के पालन के लिए और सुदृढ़ करना होगा।

घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कई और अहम फैसले भी लिए हैं। वो चाहे regulatory framework हों, regulatory frameworkमें सरलता लाने की बात हो, investor friendly policyहो, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजीस्टिक्स पर बल हो, ये सभी इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत आत्मनिर्भर बने, 21वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में एक कदम भी पीछे न रह जाए।

Make in India के साथ बढ़ता ये गौरव, नए बनने वाले वाणिज्य भवन का भी गौरव बढ़ाए, मेरी यही कामना है।

साथियों, यहां आने से पहले एक और शुभ कार्य आप लोगों ने मुझसे कराया है। इस परिसर में मौलश्री या बकुल के पौधे को लगाने का सौभाग्य मुझे मिला। मौलश्री की बहुत पौराणिक मान्यता है, कितने ही औषधीय गुणों से संपन्न है और इसका वृक्ष सालों-साल छाया देता है। मुझे बताया गया है कि इसके अलावा भी यहां करीब हजार पेड़ और लगाए जाने की योजना है।

नए बनने वाले वाणिज्य भवन का, प्रकृति के साथ ये संवाद, उसमें काम करने वाले लोगों को भी स्फूर्त रखेगा, उन्हें राहत देगा।

पर्यावरण के लिए अनुकूल, लेकिन आधुनिक तकनीक से संपन्न वातावरण में आप सभी न्यू इंडिया के लिए अपना श्रेष्ठतम दें, Best Effort करें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

एक बार फिर आप सभी को वाणिज्य भवन के निर्माण का काम शुरू होने पर बहुत-बहुत बधाई।

धन्यवाद !!!

अतुल तिवारी/ हिमांशु सिंह

(रिलीज़ आईडी: 1536291) आगंतुक पटल : 145

प्रधानमंत्री कार्यालय

प्रधानमंत्री के वीडियो ब्रिज के माध्यम से देशभर के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से संवाद का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 12 JUL 2018 5:20PM by PIB Delhi

नमस्ते।

आप आज इतनी बड़ी तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिये आए दूर दूर अपने गांव से आज करोड़ों माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। कौन होगा जिसको एक सौभाग्य के कारण ऊर्जा न मिलती हो काम करने की हिम्मत न मिलती हो। ये आप ही लोग हैं जिसका आशीर्वाद जिसका प्यार मुझे देश के लिये कुछ न कुछ करने के लिये हमेशा नई ताकत देता रहता है। आप सब अपने आप में संकल्प के धनी हैं। उद्यमशीलता के लिये समर्पित हैं। और आप टीम रूप में कैसे काम किया जाये, एक सामूहिक प्रयास कैसे किया जाए। मैं समझता हूं दुनिया की बड़ी - बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को ये मेरे हिन्दुस्तान की गरीब माताएं - बहनें जिनको शायद बहुत कम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, लेकिन वे टीम Spirit क्या होता है, मिलजुलकर के काम कैसे करना होता है, काम का बंटवारा कैसे करना होता है शायद ही इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।

महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, महिलाओं को स्वयं की शक्तियों को, अपनी योग्यता को, अपने हुनर को पहचानने का अवसर उपलब्ध हो। महिलाओं को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके भीतर बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। जिस दिन हमारी माताओं - बहनों को अवसर मिल जाता है, वो कमाल करके दिखा देती हैं सारी बाधाओं को पार कर देती हैं। और महिलाओं की ताकत देखिए क्या कुछ नहीं संभालती है वो सुबह से रात तक देखिए और कितना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो ता है उसका, अपने परिवार का गांव, समाज का जीवन बदलने के लिये उससे जो हो सकता है वो हमेशा करती है। हमारी देश की महिलाओं में सामर्थ्य है और सफलता के लिये कुछ कर गुजरने की ताकत भी रखती है, संघर्ष करने का हौसला भी है। जब भी महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। और मैं मानता हूं की महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। जिस दिन महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, तो वो assertive बनती हैं, परिवार में भी assertive बनती हैं, बच्चों को भी कहती हैं ये करो; ये मत करो, पति को भी कह सकती हैं ये करो; ये मत करो और इसलिये महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना हर निर्णय की भागीदारी बढ़ाने के लिये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसलिये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। महिलाओं में जब आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है, उसके सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो जो सामाजिक बुराइयां और जो कभी - कभी उसको सामाजिक बुराइयों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, न चाहते हुए भी बुराइयों को स्वीकार करना पड़ता है। अगर आर्थिक सामर्थ्य है, तो वो बुराइयों के खिलाफ जूझने के लिये तैयार हो जाती है। आज आप किसी भी सैक्टर को देखें, तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेंगी। कोई कल्पना कर सकता है कि

हमारी माताओं - बहनों के बिना पशुपालन का काम हो सकता है, कोई कल्पना कर सकता है कि हमारी माताओं - बहनों के योगदान के बिना हमारा कृषि क्षेत्र चल सकता है। बहुत कम लोगों को मालूम है, गांव में जाकर के देखे तो पता चलेगा कि खेती का कितना बड़ा काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। पशुपालन तो एक प्रकार से शत-प्रतिशत आज देश में जो दूध उत्पादन होता है, मैं मानता हूं शत-प्रतिशत हमारी माताओं बहनों का योगदान है। पशुपालन में परिश्रम है उसी का परिणाम है और इसलिये हमारी माताएं-बहनें खासकर के गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो रहती हैं और उनके उद्यम से लेकर कई जरूरतों को पूरा करने के लिये गांव-गांव में सामूहिक उद्यमों के क्लस्टर को बढ़ावा मिला है और ज्यादा मिलता चले जा रहा है। इन प्रयासों को गति मिले, उसके दायरे का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले।

भारत सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना,

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके तहत इसको सुनिश्चित करने के लिये काफी प्रयास कर रही है। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों के लिये श्रमिकों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वसहायता ग्रुप और मैंने देखा है बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला नहीं होगी उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है उसको समझ आता है वो अंग्रेजी में बोल लेती है। ये शब्द इतना नीचे तक पहुंच गया है। कभी स्वसहायता ग्रुप कहें तो वो सोचती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इतना वो पोप्युलर हो गया है। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह से गरीबों खास कर के महिलाओं के आर्थिक उन्नति का आधार बनी है। ये ग्रुप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत भी बना रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के ढाई लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। और मैं सभी राज्यों और वहां के अधिकारियों का भी अभिनन्दन करना चाहूंगा। जिन्होंने इस योजनाओं में लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार लाने का काम किया है। और मैं तो जो District लेवल पर हमारे काम करने वाले अफसर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने District में ऐसे जो काम होते हैं। उनकी जो इमोशनल स्टोरी होती है। एकआध किताब लिखनी चाहिए। वो सरकारी जो डोक्युमेंट है वैसा नहीं आप देखिए उन अधिकारियों को भी या उनके परिवारजनों को भी एक आनन्द आएगा कि कैसा अद्भुत काम हो रहा है। आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि अब तक महिलाओं के करीब 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए और जिनसे तकरीबन पांच करोड़ महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से पांच करोड़ परिवारों के लिये एक और कमाने वाले व्यक्ति का इजाफा हुआ है। जिससे एक और इन्कम का सोर्स तैयार हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं।

2011 से 2014 हमारी सरकार बनने के पहले अगर 2011 से 2014 तक जो कोई भी प्रगति हुई उसको अगर देखें तो पांच लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे। और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया था। हमारी सरकार बनने के बाद 2014 से 2018 तक इस काम को प्राथमिकता दी गई इस काम का महत्व माना गया और गत चार वर्ष में 20 लाख से अधिक नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और सवा दो करोड़ से अधिक परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। यानी पहले की तुलना में सेल्फ हेल्प ग्रुप चार गुना बढ़े हैं। और चार गुना अधिक परिवारों को इससे लाभ भी मिला है। यही दर्शाता है इस सरकार की काम करने की गति और जनकल्याण के लिये हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, माताओं का सशक्तिकरण हमारी कितनी प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं के ग्रुप को ट्रेनिंग से लेकर के फंडिंग और मार्केटिंग से लेकर के स्किल डेवलपमेंट में हर प्रकार की मदद दी जाती है।

जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से सेल्फ हैल्प ग्रुप के एक सदस्य आज हमारे साथ हैं। मैं फिर एक बार देश के आर्थिक विकास में भागीदारी करने वाले, परिवार के आर्थिक जीवन में योगदान देने वाले और नए नए तौर तरीकों से कम से कम खर्च से काम करने वाले, टीम बनाकर के काम करने वाले, फॉर्मल एजुकेशन हुआ हो या न हुआ हो फिर भी इस प्रकार की सफलता पर कार्य वाली इन सभी माताओं - बहनों को सुनने के लिये मैं बहुत आतुर हूँ।

देखिए कितना बदलाव आया है इन सभी के जीवन में,

सेल्फ हैल्प ग्रुप कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसका जीता-जागता उदाहरण हमें यहां देखने को मिला है। सेल्फ हैल्प ग्रुप का ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। अलग-अलग क्षेत्रों और व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और अवसर भी उपलब्ध करती है।

सेल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से एक प्रयोग महिला किसान और कृषि क्षेत्र में किया गया है। इसमें महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना पर की गई जिसके तहत 33 लाख से अधिक महिला किसानों को ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ-साथ 25 हजार से अधिक Community Livelihood Resource Person भी चुने गए। जो ग्रामीण स्तर पर 24x7 सपोर्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। आज कोई भी क्षेत्र हो खासकर कृषि से जुड़े क्षेत्रों में वैल्यु एडिशन, मूल्यवृद्धि ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे खुशी है कि आज देश के किसान मूल्यवृद्धि में वैल्यु एडिशन का महत्व समझने लगे हैं। इसे अपना रहे हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। कई राज्यों में कुछ विशेष उत्पाद जैसे मक्का, आम, फूलों की खेती, डेरी आदि के लिये वैल्यु चेन approach को अपनाया गया है। इसके लिये सेल्फ हैल्प ग्रुप से दो लाख सदस्यों को सपोर्ट किया गया है। अभी हमने पाटलिपुत्र, बिहार से अमृता देवीजी को सुना और जाना कि कैसे सेल्फ हैल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद वहां के गरीब महिलाओं के जीवन में परिवारों में कैसे बदलाव आया। मैं बिहार के ही कुछ और उदाहरण आपको बतलाता हूँ। वहां सेल्फ हैल्प ग्रुप के ढाई लाख से अधिक सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर धान की बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं। इसी तरह लगभग दो लाख सदस्य नये तरीकों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में लाख की चूड़ियां बनाने के लिये Cluster भी स्थापित किये गए हैं और प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया गया है। यह गर्व की बात है कि वहां की चूड़ियां अपने डिजाइन के लिये हमारे देश में और देश के बाहर में भी प्रसिद्ध हैं। अभी जैसा कि छत्तीसगढ़ से मीना मांझी ने बताया कि कैसे ईंट निर्माण से उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली। वहां ईंट बनाने के लिये कई यूनिट स्थापित किये गए हैं। करीब 2000 सेल्फ हैल्प ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं। हम सबको जानकर के सुखद आश्चर्य होता है कि इनका सालाना प्रोफिट करोड़ों रुपयों में पहुंचा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में 122 बिहान बाजार आउटलेट बनाए गए हैं, जहां सेल्फ हैल्प ग्रुप के 200 वैराइटी के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं।

छत्तीसगढ़ से जुड़ा मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपलोगों ने टीवी पर देखा होगा कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था, जहां मुझे ई-रिक्शा में सवारी करने का अवसर मिला। वो ई-रिक्शा एक महिला चला रही थी। छत्तीसगढ़ का वो इलाका पहले नक्सलवाद, माओवाद की हिंसा से ग्रस्त था। वहां पर आने-जाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन सरकार ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किये। और इसी का परिणाम है कि आज वहां कई ई-रिक्शा चल रहे हैं। देश में कई दुर्गम ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, जहां पर आवाजाही के लिये वाहन उपलब्ध नहीं है। इस

कार्यक्रम में ग्रामीण परिवारों को इन इलाकों में वाहन खरीदने के लिये धन उपलब्ध कराया गया। इससे आवागमन तो आसान हुआ बल्कि साथ-साथ ये ग्रामीण परिवारों के लिये आय का एक बहुत अच्छा स्रोत भी बन गया है।

देखिए हमने अभी रेवती से काफी बातें सुनीं और वंदना जी को सुना कि कैसे इस योजना के तहत कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग से उन्हें मदद मिली। ट्रेनिंग से क्या बदलाव आता है। ये उसके उदाहरण हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिये ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि देश के युवा अपनी आशा, आकांक्षा के अनुरूप आगे बढ़ सकें। स्किल ट्रेनिंग से लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देश के प्रत्येक ज़िले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, ताकि युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा उन्हें अपने घर के पास ही मिल सके। यहां गांव के युवाओं को आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। इस साल मई तक करीब - करीब 600 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं। इसके तहत करीब-करीब 28 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गयी है। और उसमें से 19-20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अभी हमने मध्य प्रदेश से सुधा बघेल जी को भी सुना। जो सेनेट्री नेपकीन्स के पैकेजिंग का काम करती हैं। मध्यप्रदेश में सेनेट्री पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए गए हैं, जो 35 जिलों में कार्यरत है। सेल्फ हैल्प ग्रुप के साढ़े पांच हजार से अधिक सदस्य इस काम को कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं। वहां करीब 500 आजीविका फ्रेश स्टोर्स खोले गए हैं। जहां हर वर्ष एक टन से अधिक आजीविका मसालों की बिक्री होती है। एक तरह से वहां आजीविका एक ब्रांड बन गया है। अभी हमने रेखा जी से बात कि और जाना की कैसे सेल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से एक प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में किया गया है। गांव या दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग या वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिये सेल्फ हैल्प ग्रुप के सदस्य को बैंक मित्र के रूप में बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज करीब 2000 सेल्फ हैल्प ग्रुप्स देश भर में बैंक मित्र या बैंक सखी बैंकिंग सहायक के रूप में काम कर रहा है। मुझे बताया गया कि इससे करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का लेनदेन हुआ है।

देखिये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कैसे काम होता है, आपको मालूम ही है कि कई महिलाएं ऐसी हैं, जो इस कार्य से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। वो इस कार्यक्रम को खुद तो चलाती हैं साथ ही कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में नये गांवों में भी जाकर वहां की महिलाओं को इसके लिये प्रेरित करती हैं। अभी तक 2 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा इस कार्यक्रम को पूरे देश में आगे बढ़ाया जा रहा है और ये संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ रही है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान के अलावा बैंकों द्वारा ऋण दिलाये जाने का भी प्रावधान है। बैंकों से मिलने वाले लोन से लोगों को व्यवसाय को बढ़ाने में काफी लाभ मिलता है। साथ में एक बात जो आप सभी को अच्छी लगेगी कि लोन का वापस भुगतान यानि रिपैमेंट में भी समय पर किया जा रहा है।

और मैंने देखा है कि कभी भी ये सेल्फ हैल्प ग्रुप के पैसे पहुंचने में कभी बैंक को देर नहीं आई। करीब करीब 99 पर्सेंट पैसे वापस आ गए। ये हमारे गरीब परिवार के संस्कार होते हैं। गरीबों की अमीरी है, जिसमें ये ताकत है। अभी हमने लक्ष्मी जी से सुना कि कैसे और उनके साथ तीस अन्य महिलाएं पापड़, अपना प्रोडक्ट बेच कर कैसे मुनाफा कमा रही हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस विशेष पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि सेल्फ हैल्प ग्रुप के उत्पाद सही दामों पर बिके। उनके लिये अच्छे बाजार उपलब्ध हों। इसके लिये भारत सरकार हर राज्य में प्रति वर्ष दो सरस मेलों के आयोजन

के लिये अनुदान देती है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हर वर्ष सेल्फ हैल्प ग्रुप के उत्पादों की मांग बढ़ रही है। जिससे उनके आय में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को जेम (जी ई एम) यानी गवर्मेंट ई मार्केट से भी लाभ मिल रहा है। पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ाना और उसको बढ़ावा देने के लिये सरकार डीजिटल तरीके से सामानों की खरीद बिक्री को बढ़ावा देगी। सरकार में अब इसी के जरिये टेंडर दिये जा रहे हैं और सरकारी सामान की खरीदी हो रही है। और इसके लिये मैं सभी सेल्फ हैल्प ग्रुप की बहनें जो आप कुछ न कुछ उत्पाद करती हैं कुछ न कुछ प्रोडक्ट करती हैं, आप ये सरकार को जो पोर्टल है जीईएम उसमें जाकर के अपने आपको रजिस्टर करवा दीजिए, ताकि आप भी अगर सरकार को किसी चीज की जरूरत हो उसकी जानकारी आ जाए तो आप भी कह सकती हैं कि आप भी प्रोवाइड कर सकती हो और सरकार खरीदती है इन चीजों को।

देखिए अगर वो भेंड़ पालते हैं और ऊन बेचते हैं, तो मैं एक सुझाव देता हूँ आपको। मैं जब गुजरात में था, तो मैंने एक छोटा प्रयोग किया और उस प्रयोग का ये जो भेंड़, बकरी चराने वाले और छोटे-छोटे काम करने वाले लोग थे, तो आपने देखा होगा आजकल ये बड़े - बड़े सैलून होते हैं, वहां जो हजामत करने वाले लोग होते हैं, वो एक मशीन होती है ट्रिंमर हमलोग जो दाढ़ी को ठीक करते हैं ट्रिंमर उपयोग करते हैं, तो मैंने ऐसे ट्रिंमर इन भेंड़ चराने वालों को दिया, और मैंने कहा कि आप कैंची से जो बाल काटते हैं भेंड़ के तो उसके ऊन के टुकड़े हो जाते हैं, तो आपको कमाई कम होगी। आप ये ट्रिंमर से मशीन से काटिए तो लंबे तार वाला ऊन मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे उसके कारण मेहनत भी कम हो गई। उस भेंड़ को तकलीफ होती थी वो भी कम हो गई। और लंबे धागे के ऊन मिलने लगे उनको मार्केट में अच्छा मिलने लगा। आपके यहां जो बहनें हैं। उनको ये अगर ट्रेनिंग करवा लेती हैं, तो ये आपके यहां तो ऊनी चीजों गर्म कपड़ों का काफी काम है, अच्छे धागे बन सकते हैं, तो बहुत बड़ी कमाई हो सकती है, तो आप जरूर वहां इस दिशा में सोचिए कुपवाड़ा इलाके में जो पहले मैंने देखा है कि इस काम को काफी ताकत थी और दूध के क्षेत्र में भी आपके इलाके में भी काफी मदद मिलती थी।

आप लोगों की कहानियां आप लोगों के अनुभव मैं समझता हूँ जो भी सुनेगा और अगर खुले मन से सुनेगा अच्छा सोचने की भूमिका से सुनेगा तो मैं जरूर मानता हूँ। हमारे देश की माताओं बहनों की ताकत कितनी है थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो कैसे अपनी दुनिया खड़ी कर सकती हैं। कैसे मिलजुलकर के काम कर सकते हैं। कैसे लीडरशिप दे सकते हैं। एक नए भारत की नींव रखने के लिये वो कैसा परिश्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सुनने वाले हम सबके लिये इनकी एक-एक गाथा बहुत ही प्रेरक है। इससे देश को ताकत मिलती है। इससे हमारी हर महिला को कुछ नया करने का रास्ता मिलता है, उत्साह मिलता है। और निराशा फैलाने वालों की संख्या कम नहीं। बुराई फैलाने वालों की संख्या कम नहीं। लेकिन अच्छाई का रास्ता छोड़ना नहीं। परिश्रम करने वालों की पूजा करना छोड़ना नहीं। अपने बलबूते में देश को आगे बढ़ाना, अपने को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, कठिन जिंदगी से निकल कर जीना ये अपने आप में हर इंसान को निराशा से जूझने की ताकत देता है और देश की यही तो ताकत है। और इसलिये मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर के उससे मुझे भी ऊर्जा मिली है। मुझे प्रेरणा मिली है और मुझे विश्वास है कि आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो बातें बताई हैं। और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत लोग हैं जिनको कहना है। हर किसी की अपनी एक कथा है हर किसी का अपना अनुभव है। हर किसी ने मुसीबतों से रास्ता निकाला है और ये आपका काम है आपका परिश्रम है आपकी हिम्मत है। किसी को इसकी क्रेडिट नहीं जाती है सिर्फ आपको ही जाती है और इसलिये आप से बढ़कर के कोई प्रेरणा नहीं है। लेकिन जिन बातों को बहनों को बहुत कुछ कहना है वो कह नहीं पाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। मैं आपको सुनूंगा। और कभी जो मैं आप में से मेरी जो बात आपसे आई होगी मन

की बात में भी कभी सुनाऊंगा। क्योंकि देश को इसी से प्रेरणा मिलती है। रोग धोना करने वाले करते रहते हैं। अच्छा करने वाले भी प्रेरणा देते हैं। अब उसको काम लेकर के आगे चलना है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपके पास मोबाइल फोन का उपयोग करने की आदत लग गई होगी। अगर नहीं लगी है तो आपके यहां कॉमन सर्विस सेंटर होता है। आपने देखा होगा नरेन्द्र मोदी एप है। आप उस पर जाकर के आप अपने समूह की फोटो रखिए। आप अपने समूह की बहनों की इन्टरव्यू उसमें बोलकर के रखिए। क्या काम किया कैसे किया। कैसे मुसीबतों से आप निकले और क्या-क्या अच्छा काम किया है। ये सब आप उस पर डाल दीजिए। मैं इसको देखूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा और आप उसमें डालोगे तो लोग भी देखेंगे और फिर मैं उसमें से दो चार बातें जब भी मुझे मन की बात में से समय निकलेगा मैं जरूर आपकी बातें दुनिया को बताऊंगा। आपने अपने लिये तो किया ही है, लेकिन आपने ऐसी करोड़ों करोड़ों बहनों को भी एक नई हिम्मत दी है, नया हौसला दिया है। अब तो कॉमन सर्विस सेंटर बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। देश के तीन लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर हैं। अब तो हमारी बेटियां ही कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। वहां जाकर के आप इस टैक्नॉलॉजी का उपयोग करके आपकी जो सफलता की गाथा है वो जरूर मुझे भेजिए सारा देश और दुनिया उसको देखेगी। कैसे-कैसे हमारे दूर-सुदूर गांव में रहने वाली बहनें भी कितना उत्तम काम कर रही हैं। कैसे-कैसे नए तरीके ढूंढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों को मिलने का मौका मिला। आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको बहुत-बहुत बधाई है।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

एकेटी/वीजे/एसए

(रिलीज़ आईडी: 1538470) आगंतुक पटल : 591

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , Assamese , Tamil

प्रधानमंत्री कार्यालय

तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के शुभारम्भ अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 01 SEP 2018 10:55PM by PIB Delhi

मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, श्रीमान मनोज सिन्हा जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सीईओ, सेक्रेटरी पोस्ट IPPB के तमाम साथी यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों। इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशभर के तीन हजार से अधिक सेंटर पर पोस्टल विभाग के हजारों कर्मचारी और अन्य भी यहां के नागरिक और जैसा हमारे मनोज जी ने बताया करीब 20 लाख लोग इस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वहां कई राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र के मंत्रिपरिषद के हमारे साथी, राज्य के मंत्रिगण, सांसदगण, विधायकगण, ये सब भी वहां मौजूद हैं, मैं उन सबका भी इस समारोह में स्वागत करता हूं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं।

हमारे मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी II Tian हैं और आईआईटी में पढ़े-लिखे होने के कारण वो स्वभाव से हर चीज़ में टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं और इसलिए यह समारोह भी टेक्नोलॉजी से भरपूर है और साथ-साथ यह initiative भी टेक्नोलॉजी वाला है। और मनोज जी ने व्यक्तिगत रूचि ले करके इस काम को आगे बढ़ाया। उनका अपना टेक्नोलॉजी का background होने के कारण बहुत ही उत्तम प्रकार के उनके input मिले और उसका नतीजा है कि आज देश को एक बहुत बड़ा नजराना मिल रहा है। और आज 01 सितंबर, देश के इतिहास में एक नई और अभूतपूर्व व्यवस्था की शुरुआत होने के नाते याद किया जाएगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से देश के हर गरीब, सामान्य मानव तक देश के कौने-कौने तक, दूर-दराज के पहाड़ों पर बसे लोगों तक, घने जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों तक, दूर किसी द्वीप में रहने वाले उन समूहों तक यानि एक-एक भारतीय के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, एक प्रकार से आज वो मार्ग इस प्रारंभ से खुल गया है। इस नई व्यवस्था के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

भाइयों-बहनों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक देश के अर्थतंत्र में सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया और आज इस initiative से हम बैंक को, गांव और गरीब के दरवाजों तक पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। आपका बैंक आपके द्वार यह सिर्फ एक घोष वाक्य नहीं है, यह हमारा commitment है, हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाये जा रहे हैं। देशभर के साढ़े छह सौ जिलों में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखाएं प्रारंभ हो रही हैं और हमारी चिट्ठियां लेना वाला डाकिया अब चलता-फिरता बैंक भी बन गया है।

अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने यहां एक प्रदर्शनी देखी, क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे काम होना है, इस बारे में विस्तार से मुझे बताया गया और हो सकता कि वो आपने भी स्क्रीन पर देखा होगा। और जब मैं इसे देख रहा था वहां जो विशेषज्ञ थे जो मुझे इस सारी योजना को समझा रहे थे और तब एक विश्वास, मेरे भीतर एक आत्म संतोष का भाव जग रहा था कि ऐसे साथियों के साथ रह करके उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका यह प्रयास जरूर नया रंग लाएगा। और मुझे याद है कि एक जमाना था और डाकिये के संबंध में मैं समझता हूं कि हमारे यहां बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा, लेकिन डाकिये के प्रति कभी विश्वास नहीं डगमगाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो लोग ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे उनको पता होगा कि दशकों

पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो उसके हाथ में एक भाला रहता था, भाले पर एक घुंघरू बंधा रहता था, और वो चलता था तो घुंघरू की आवाज आती थी। एक गांव से जब दूसरे गांव जब डाकिया जाता था और घुंघरू की आवाज आती थी, तो वो इलाका कितना ही घना हो, कितना ही दुर्गम हो, कितना ही संकटों से भरा हो, डकैत हो, आते हो-जाते हो, चोर-लूटेरें रहते हो, लेकिन जब घुंघरू की आवाज आती थी कि डाकिया है, कोई चोर-लूटेरा उनको परेशान नहीं करता था। उन चोर-लूटेरों को भी पता था कि डाकिया किसी गरीब मां के लिए मनी ऑर्डर ले करके जा रहा है।

आपको मालूम होगा, अभी तो हर घर में कौने में घड़ी पड़ी होगी, लेकिन पहले गांव में शायद एक-आध टावर हो तो घड़ी होती थी, वरना घड़ी कहां होती थी। और मैं वो जिंदगी जी करके आया हूं तो मुझे मालूम है कि जो बुजुर्ग लोग अपने घर के बाहर बैठे रहते थे और जरूर पूछते थे- डाकिया आ गया क्या? शायद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होगा जो दिन में दो-चार बार पूछता नहीं हो, कि डाकिया आ गया क? लोगों को लगता होगा कि क्या उनकी कोई डाक आने वाले है, डाक तो आती नहीं, लेकिन वो डाक के लिए नहीं पूछता था उसे मालूम था कि डाकिया आ गया मतलब घड़ी में इतना टाइम हुआ होगा, यानी समय की पाबंदी। डाकिया आया या नहीं आया इसके आधार पर हमारी समाज व्यवस्था में तय होती थी और इसलिए एक प्रकार से डाकिया हर परिवार से एक emotional connect चिट्ठियों से जुड़ा होता था, और इसलिए डाकिये को भी समाज में एक विशेष स्वीकार्यता और सम्मान प्राप्त था।

आज के इस युग में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन चिट्ठियों को ले करके डाकिया जो भावना, जो विश्वसनीयता पहली थी आज भी वैसी ही है। डाकिया और पोस्ट ऑफिस एक प्रकार से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारी फिल्मों का, हमारे साहित्य का, हमारी लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम सभी ने अभी जो advertisement दिखा रहे थे - 'डाकिया डाक लाया', ऐसे गीत दशकों तक लोगों को अपने जीवन का हिस्सा लगते रहे हैं। अब आज से डाकिया डाक लाया के साथ-साथ डाकिया बैंक भी लाया है।

दशकों पहले मैं एक बार कनाडा गया था, तो मुझे कनाडा में एक फिल्म देखने को मिली थी, मुझे आज भी याद है, उस फिल्म का नाम था AirMail और सचमुच में रोंगटें खड़े कर देने वाली फिल्म है, डाक के ऊपर है। और हमारे जीवन में अपनों की चिट्ठियों का जो महत्व है वो इस फिल्म की कहानी का आधार था। फिल्म में एक हवाई जहाज था, जिसमें चिट्ठियां जा रही थी लेकिन वो दुर्भाग्य से crash हो गया, इस हादसे के बाद जो हवाई जहाज crash हुआ था, उसमें जो चिट्ठियां थी, उसको बटोर करके उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कथा उस movie में है। किस प्रकार से उन चिट्ठियों का जतन किया गया था और ऐसे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, वैसी कोशिश डाकिये उन चिट्ठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। हो सकता है शायद आज भी youtube पर यह movie हो तो आप जरूर देखिएगा। और उन पत्रों में कितनों का दुलार था, संदेश था, चिंता थी, शिकायतें थी। चिट्ठियों में आत्मीयता ही उसकी आत्मा होता है। आज भी मुझे सैकड़ों की संख्या में हर रोज चिट्ठियां मिलती हैं। पोस्ट विभाग का भी काम बढ़ गया है, मैं जब से आया हूं। कोई चिट्ठी तब लिखता है न जब उसको भरोसा हो। और मेरा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है, उसको ले करके भी हर महीने हजारों चिट्ठियां आती हैं। यह पत्र लोगों के साथ मेरा सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जब वो चिट्ठियां पढ़ता हूं, तो लगता है कि लिखने वाला सामने ही है, अपनी बात सीधे ही मुझे कह रहा है।

साथियों, हमारी सरकारी की approach समय के साथ चलती है। भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किये हैं। हम वो पुरातन पंथी नहीं हैं, हम समय के साथ बदलने वाले लोग हैं। हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं। देश की, समाज की, समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के पक्ष में हैं। जीएसटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसे अनेक प्रयासों की कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक भी अब जुड़ गया है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ने वाली नहीं, बल्कि reform, perform और उन्हें transform करने का काम कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी के माध्यम से.. और माध्यम भी बदले हैं, भले बदले हो, लेकिन मकसद तो अब भी वही है। अंतरदेशीय पत्र या Inland Letter की जगह अब भले ई-मेल ने ले ली हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। और इसलिए जिस

टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ऑफिस को चुनौती दी, क्योंकि लोगों को लग रहा था अब यह डाक विभाग रहेगा नहीं रहेगा, डाकिये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनकी नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी.. इनकी चर्चा चल रही थी। टेक्नोलॉजी ने जो चुनौती दी, उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदलने के प्रति आगे बढ़ रहे हैं।

भारतीय डाक विभाग, देश की वो व्यवस्था है जिसके पास डेढ़ लाख से अधिक डाक घर हैं। इनमें से भी सवा लाख से अधिक सिर्फ गांव में ही है। तीन लाख से अधिक पोस्ट मेन और ग्रामीण डाक सेवक, देश के जन-जन से जुड़े हुए हैं। इतने व्यापक नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़ कर 21 वीं सदी में सेवा का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बनाने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। अब डाकिये के हाथ में स्मार्ट फोन है और उसके थैले में, उसके बैग में एक डिजिटल डिवाइस भी है। साथियों, एकता, समानता, समावेश सेवा और विश्वास का प्रतीक यह पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है। IPPB में बचत खाते के साथ-साथ, छोटे से छोटा व्यापारी अपना काम चलाने के लिए चालू खाता भी खोल सकता है। यूपी और बिहार का जो कामगार मुम्बई या बेंगलुरु में काम कर रहा है, वो आसानी से पैसा अपने परिवार को भेज पाएगा। दूसरे बैंक खातों में पैसा भी वो ट्रांसफर कर सकता है। सरकारी सहायता का पैसा मनरेगा की मजदूरी के लिए भी इस खाते का उपयोग वो आसानी से कर सकता है। बिजली और फोन के बिल जमा करने के लिए भी उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही नहीं दूसरे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ऋण भी दे पाएगा। निवेश और बीमा जैसी सेवाएं भी अपने ग्राहकों को पहुंचाएगा। सबसे अहम बात यह है कि सभी सेवाएं बैंक के काउंटर के अतिरिक्त घर आकर डाकिये देने वाले हैं। बैंक से संवाद, डिजिटल लेन देने में जो भी मुश्किल अभी तक आती थी, उनका समाधान भी डाकिये के पास रहेगा। आपने कितने पैसे जमा किये थे, आपको कितना ब्याज मिला, कितने पैसे आपके खाते में बचे हैं यह सब अब घर बैठे-बैठे डाकिया बता देगा। यह सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, मध्यम वर्ग का विश्वस्त सहयोगी सिद्ध होने वाला है।

अब आपको अपना खाता, अपने खाते का नंबर, याद रखने की, किसी को पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुए इस बैंक की सारी प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया गया है। इस नये बैंक में कुछ ही मिनटों में आपका खाता खुल जाएगा। और हमारे मंत्री जी कहते थे, ज्यादा से ज्यादा एक मिनट। इसके साथ ही खाता धारक को एक QR कार्ड दिया जाएगा, जो मुझे अभी दिया गया है, क्योंकि मेरा भी खाता खुल गया है। जो खाता नहीं है, वो भी खाता तो रखता ही है।

आपको हैरानी होगी हमारे जीवन में बैंक अकाउंट का कभी नाता नहीं आया, लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे तो देना बैंक की एक स्कीम थी, वो एक गुल्लक देते थे बच्चों को और एक अकाउंट खोलते थे, तो हमें भी दिया, लेकिन हमारा तो खाली रहा हमेशा। बाद में हम गांव छोड़कर चले गए, लेकिन बैंक अकाउंट खाता बना रहा और बैंक वालों को हर साल उसको carry forward करना पड़ता था। बैंक वाले मुझे ढूंढ रहे थे, खाता बंद करने के लिए। मेरा कोई अतापता नहीं था। करीब 32 साल के बाद उनको पता चला कि मैं कहीं आया हूं, तो बैंक वाले बिचारे वहां आये, बोले भाई signature कर दो हमें तुम्हारा खाता बंद करना है। खैर बाद में जब गुजरात में MLA बना तो तन्हाह आने लगा तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, लेकिन उससे पहले कभी नाता ही नहीं आया और आज पोस्ट वालों ने एक और खाता खोल दिया।

देखिए डाकिया सिर्फ डाक पहुंचाता था, ऐसा नहीं है। जो परिवार पढ़े-लिखे नहीं होते थे, तो डाकिया बैठ करके, डाक खोल करके पूरी सुना करके जाता था, फिर वो बूढ़ी मां कहती थी कि बेटा वो बेटे को जवाब लिखना है तो कल तुम एक पोस्ट कार्ड ले आना और मैं जवाब बताऊंगी, तो दूसरे दिन वो डाकिया पोस्ट कार्ड भी ले करके आता था और वो मां लिखवाती थी, वो लिख देता था। यानी कैसी आत्मीय व्यवस्था, वही टेक्नोलॉजी का काम मेरा डाकिया फिर से एक बार करेगा। यानी एक QR कार्ड आपकी ऊंगली का निशान और डाकिये की जुबान, बैंकिंग को आसान और हर आशंका का समाधान करने वाली है। साथियों गांव में सबसे मजबूत नेटवर्क होने की वजह से IPPB किसानों के लिए भी एक बड़ी सुविधा सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को इससे विशेष बल मिलेगा। Claim कों समय पर settle करना हो या किसानों को इस स्कीम से जोड़ना हो निश्चित

रूप से इस बैंक से लाभ होने वाला है। पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के बाद अब योजनाओं की claim राशि भी घर बैठे ही मिला करेगी। इसके अलावा यह बैंक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम पर पैसा बचाने की मुहिम को भी गति देगा।

भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश के बैंकों को गरीब के दरवाजे पर ले करके आ गई है। वरना चार-पांच साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बैंकों का अधिकांश पैसा सिर्फ उन्हीं इने-गिने लोगों के लिए रिजर्व रख दिया गया था जो किसी एक परिवार के करीबी हुआ करते थे। आप सोचिए आजादी के बाद से लेकर 2008 तक यानी 1947 से 2008 तक और देशभर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुन करके चौंक जाएंगे 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिला करके 18 लाख करोड़ रुपये की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में, लेकिन 2008 के बाद, सिर्फ छह साल में यानी 60 साल में क्या हुआ और छह साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और छह साल में यह राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। ले जाओ। बाद में मोदी आएगा, रोयेगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था उसको लगभग दोगुना लोन पिछले सरकार के छह साल में...तेरा भी भला, मेरा भी भला। और यह लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में यह टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक special परंपरा चल रही थी, फोन बैंकिंग की। और उस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था। अनेक नामदर अगर फोन कर दे तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बेड़ा पार...लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी, धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था, वो नामदरों से बैंक में फोन करवा देता था। बैंक वाले उस व्यक्ति या कंपनी को जड़ से अरबों-खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम, सारे कायदा-कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलिफोन। कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह भी उठता है कि बैंकों ने इस तरह की फोन बैंकिंग से मना क्यों नहीं किया। साथियों, आपको यह पता है कि उस समय बैंकों में नामदारों के आशीर्वाद से ही अधिकांश लोगों की नियुक्ति होती थी। नामदरों के प्रभाव की वजह से ही बैंक के बड़े-बड़े दिग्गज भी लोन देने से मना नहीं कर पाते थे। छह साल में लगभग दोगुना लोन देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। बैंकों ने यह जानते हुए भी कि उनके द्वारा दिये गये लोन की वापसी मुश्किल होगी, बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा। पता है नहीं आएगा, दो। इतना ही नहीं, जब ऐसे लोग कर्ज चुकाने में default करने लगे तो बैंकों में फिर से दबाव आया, उन्हें नये लोन दीजिए, और यह गोरखधंधा, यह चक्र लोन की restructuring के नाम पर हुआ। यानी एक बार लोन ले लिया फिर जहां पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब उसको फिर वो मांग रहा है कि दूसरा दो, तो मैं देता हूं। वो देता है, यह देता है, यह देता है, यह देता है। वो ही चक्र चलता था। जो लोग इस गोरखधंधे में लगे थे, उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि एक न एक दिन उनकी पोल जरूर खुलेगी और इसलिए उसी समय से हेरा-फेरी की एक और साजिश साथ-साथ रची गई, बैंकों का दिया कितना कर्ज वापस नहीं आ पा रहा, इसके सही आंकड़े देश से छिपाये गए। देश को अंधेरे में रखा गया। यानी जो लाखों-करोड़ों रुपये फंसे थे उसे कागजों पर सही तरीके से नहीं बताया गया, छुपाया गया। देश से झूठ बोला गया कि सिर्फ दो लाख करोड़ रुपये हैं, जो आना बाकी है और शक है कि आएंगे या नहीं आएंगे। जिस समय देश में बड़े-बड़े घोटाले उजागर हो रहे थे, उस समय पिछली सरकार ने सारी मेहनत अपने यह सबसे बड़े घोटाले को छिपाने में लगाई हुई थी। बैंकों में कुछ खास लोग भी इसमें नामदारों की जरा मदद कर रहे थे।

2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सारी सच्चाई सामने आने लगी, तब बैंकों से कड़ाई से कहा गया कि सही-सही आकलन करके उनकी कितनी राशि, इस तरह का लेनदेन और उनका लोन देना बाकी है, कितने रुपये फंसे हुए हैं, सारी जानकारी लाओ। छह साल में जो राशि दी गई उसकी सच्चाई यह है कि जिस राशि को पिछली सरकार सिर्फ दो-ढ़ाई लाख करोड़ बता रही थी, वो दरअसल नौ लाख करोड़ रुपया थी। चौंक जाएगा आज देश सुन करके, देश के साथ कितना धोखा किया गया। देश के सामने कितना झूठ बोला गया। हर रोज़ ब्याज की रकम जुड़ने की वजह से यह दिनों-दिन और बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज तो जुड़ना ही जुड़ना है, बैंक तो अपना कागजी काम तो करेगा ही करेगा।

साथियों, 2014 में सरकार बनने के कुछ समय बाद ही हमें एहसास हो गया था कि कांग्रेस का और यह नामदार देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी land mine बिछा करके गया है। अगर उसी समय देश और दुनिया के सामने इसकी सच्चाई रख दी जाती तो ऐसा विस्फोट होता कि अर्थव्यवस्था शायद संभालना मुश्किल हो जाता। इतनी बर्बादी कर रखी थी। इसलिए बहुत ऐहतियात के साथ, बड़ी बरीकी के साथ काम करते-करते इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम दिन-रात लगे रहे।

भाइयों और बहनों, हमारी यह सरकार, एनपीए की सच्चाई, पिछली सरकार के घोटले को देश के सामने ले करके आई है। हमने केवल बीमारी का पता ही नहीं लगाया, बल्कि उसके कारण की भी तलाश की और उस बीमारी को दूरस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पिछले साढ़े चार साल में 50 करोड़ से बड़े सभी लोन की समीक्षा की गई। लोन की शर्तों का बड़ी कड़ाई से पालन हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कानून बदलें। बैंकों के मर्जर का निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्टर में professional approach को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए निरंतर सुधार किये जा रहे हैं। Fugitive Economic Offenders Bill, भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यह भगोड़े अपनी संपत्ति में खुद भाग न ले सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। बड़े लोन लेने वालों के पासपोर्ट detail भी अब सरकार के कब्जे में रखना तय कर लिया है, ताकि देश छोड़ करके भागना उनके लिए आसान न हो। Bankruptcy कोड और एनसीएलटी द्वारा NPA की recovery शुरू हुई है। 12 सबसे बड़े defaulters, जिनको 2014 के पहले लोन दिया था, जिसकी NPA की राशि करीब-करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये है उनके खिलाफ तेज गति से कार्रवाई चल रही है। अब उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसी प्रकार उन 12 के अलावा और दूसरे 27, वो भी बड़े-बड़े लोन खाते वाले हैं, जिनमें लगभग एक लाख करोड़ रुपये का एनपीए है। इनकी वापसी का भी इंतजाम बहुत पक्के तरीके से हो रहा है। जिनको लग रहा था कि नामदारों की सहभागिता और मेहरबानी से उनको मिले लाखों-करोड़ों रुपया हमेशा-हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे, हमेशा incoming ही रहेगा, अब उनके खाते से outgoing भी शुरू हुआ है। देश में एक नया बदलाव आया है। अब एक नया culture आया है, culture बदल रहा है। पहले बैंक इनके पीछे पड़ते थे। अब हमने कानून की जाल ऐसी बनाई है कि अब वो re-payment करने के लिए चक्कर काट रहे हैं। कुछ करो भाई, थोड़ा ले लो, थोड़ा अगले महीने दे दूंगा, कोई बचा लो मुझे। अब यह खुद बैंक के पीछे दौड़ने लगे हैं। पैसा वापस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिनों-दिन मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था के साथ ही अब ऐसे लोगों पर जांच एजेंसियां का शिकंजा और कसने जा रहा है और मैं देश को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सारे बड़े लोनों में से एक भी लोन इस सरकार का दिया हुआ नहीं है। हमने तो आने के बाद बैंकों की दिशा और दशा दोनों में निरंतर बदलाव किया है। और आज का यह आयोजन भी उसी का एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले नामदारों के आशीर्वाद से यह बड़े लोगों ही कर्ज मिलता था। अब देश के गरीब को बैंक से कर्ज मिलना हमारे डाकिये के हाथ में आ गया।

पिछले चार साल में मुद्रा योजना के माध्यम से 13 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज स्वरोजगार के लिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को दिया गया है। 32 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 21 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सिर्फ एक रुपया, महीने का एक रुपया और 90 पैसे प्रति दिन के प्रीमियम पर बीमा और पेंशन का सुरक्षा कवच भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

भाइयों और बहनों, देश की अर्थव्यवस्था को जिस land mine पर नामदारों ने बिठाया था, उस landmine को हमारी सरकार ने निष्कर्ष कर दिया है। देश आज एक नये आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक तरफ इस एशियन गेम्स में भारत ने अपनी best ever performance दिखाई, हमारे खिलाड़ियों ने, तो दूसरे तरफ कल देश को अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से भी एक नया मेडल मिला है। जो आंकड़े आए हैं, वो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और उसमें आते आत्मविश्वास के प्रमाण हैं। 8.2 percent की दर से हो रहा विकास, भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। एक नये भारत की उज्ज्वल तस्वीर को सामने लाता है। यह आंकड़े न सिर्फ अच्छे हैं, बल्कि सभी जो expert लोग हैं, अनुमान लगाते थे, उससे भी ज्यादा अधिक है। जब देश सही दिशा में चलता है और नीयत साफ होती है, तो ऐसे ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों यह मुमकिन

हुआ है सवा सौ करोड़ देशवासियों की मेहनत से, लगन और commitment के कारण। हमारे युवाओं, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे मजदूर, यह हम सबका, उन सबके पुरूषार्थ का परिणाम है कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

आज भारत न सिर्फ देश की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था है, बल्कि सबसे तेजी से गरीबी मिटाने वाला देश भी बना है। जीडीपी के आंकड़े गवां है कि नया भारत अपने सामर्थ्य के बूते सवा सौ करोड़ भारतीयों के संघर्ष और समर्पण के दम पर आगे बढ़ रहा है। मैं देश को फिर कहना चाहूंगा कि बैंकों का जितना भी पैसा नामदारों ने फंसाया था, उसका एक-एक रुपया वापस ले करके ही रहने वाले हैं। उससे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा।

IPPB और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंकिंग, बीमा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, direct benefit transfer, passport सेवा, online shopping जैसी अनेक सुविधाएं गांव-गांव, घर-घर और प्रभावी तरीके से पहुंचने वाली है। यानी 'सबका साथ, सबका विकास' रास्ते को हमारा डाकिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सशक्त करने के लिए अब एक नये रूप में देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस विराट मिशन को गांव-गांव, घर-घर तक, किसान तक, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए देश के तीन लाख डाक सेवक कटिबद्ध हो करके तैयार हैं। डाक सेवक लोगों को डिजिटल लेन-देन में न केवल सहयोग करेंगे, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि भविष्य में वो अपने फोन से खुद बैंकिंग और डिजिटल transaction कर सकें। इस तरह हमारे डाक बाबू न सिर्फ बैंकर होंगे, बल्कि देश के डिजिटल टीचर भी बनने वाले हैं। देश की सेवा करने वालों की इस भूमिका को देखते हुए बीते महीनों में सरकार ने भी कई अहम फैसले लिये हैं। सरकार ने जुलाई में ही ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों से जुड़ी पुरानी मांग को पूरा किया है। इसका लाभ देश के ढाई लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। पहले उन्हें जो समय संबंधी भत्ता मिलता था, उसमें दर्जन भर स्लैब होती थी। अब इसे भी घटाकर सिर्फ तीन कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें जो भत्ता दो से चार हजार के बीच मिलता था, उसे बढ़ाकर 10 हजार से 14 हजार रुपये कर दिया गया है। वो जिस मुश्किल परिस्थिति में काम करते हैं, उसे देखते हुए एक नये भत्ते की भी शुरूआत की गई है। जो महिला ग्राम डाक सेवक हैं, उन्हें पूरे वेतन के साथ 180 दिन यानी छह महीने के मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रयासों की वजह से ग्रामीण डाक सेवक के वेतन में औसतन 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मुझे बताया गया है कि डाक सेवक के रिक्त पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। यह फैसले इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक के हमारे सबसे मजबूत प्रतिनिधि को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

साथियों, आज देश के तीन हजार से अधिक स्थानों पर यह सेवा शुरू हो रही और जैसे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि आने वाले कुछ ही महीनों में डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस इस सुविधा से जुड़ जाएंगे। New India की इस नयी व्यवस्था को देश के मजबूत telecom infrastructure से भी मदद मिलेगी। देशवासियों को इस नई व्यवस्था के लिए, नये बैंक के लिए, नई सुविधा के लिए बहुत-बहुत बधाई के साथ मैं फिर एक बार डाक के सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। Postal Department के हर कर्मचारी, इस बैंक से जुड़े हर व्यक्ति को मैं पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, और मनोज सिन्हा जी को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनका आईआईटी को background इस काम में मुझे बहुत मदद की। टेक्नोलॉजी ने भरपूर मदद की है। और इसके लिए मंत्री जी को भी नेतृत्व देने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।

अतुल कुमार तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्मीकि महतो/तारा

(रिलीज़ आईडी: 1547051) आगंतुक पटल : 129

प्रधानमंत्री कार्यालय

गंतव्य उत्तराखंड: निवेशक सम्मेलन 2018 में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 07 OCT 2018 12:21PM by PIB Delhi

उत्तराखंड के राज्यपाल, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, केन्द्रीय मंत्रीपरिषद के मेरे तमाम सहयोगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेन्द्र सिंह जी रावत, उत्तराखंड केबिनेट के सभी सदस्यगण, सिंगापुर के सूचना प्रसारण मंत्री श्री एस.ईश्वरन जी, जापान एवं चैक रिपब्लिक के राजदूत, देश-विदेश से पधारे तमाम उद्यमी साथियो, देवियो और सज्जनों।

बाबा केदार की छत्रछाया में चार धाम की पवित्रता के लिए देवधरा उत्तराखंड में पधारे देश-विदेश के सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिवादन है। मुझे विश्वास है कि आप यहां भारत के economic environment के साथ-साथ हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी cultural diversity को और prosperity से उसकी अनुभूति करेंगे, उसका परिचय करेंगे और एक नई चेतना प्राप्त करके यहां से लौटेंगे।

साथियो, उत्तराखंड की इस धरती पर हम सभी ऐसे समय पर एकत्र हुए हैं जब भारत में तेज गति से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ रहा है। देश बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम नए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी संस्था कह रही है कि भारत आने वाले दशकों में world growth का प्रमुख engine बनने वाला है। आज भारत की अर्थव्यवस्था और स्थिर हुई है। Fiscal deficit कम हुआ है, महंगाई दर नियंत्रण में है। हमारे यहां दुनिया में सबसे तेज गति से middle class का bulk, middle class का प्रसार हो रहा है। 80 करोड़ से अधिक युवा, ये शक्ति demographic dividend, आकांक्षाओं और सामर्थ्य से भरपूर है।

साथियो, आज भारत में जिस speed और skill पर आर्थिक सुधार हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व हैं। पिछले दो वर्षों में ही केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दस हजार से ज्यादा कदम उठाए गए हैं। इन कदमों की वजह से भारत ने ease of doing business, इसमें 42 अंकों का सुधार किया है। उस सुधार की प्रक्रिया में हमने 1400 से ज्यादा कानून खत्म किए हैं। इसके अलावा भारत में टैक्स व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए गए हैं। टैक्स से जुड़े मामलों के समाधान को और पारदर्शी और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है।

Insolvency और bankruptcy code से आज कारोबार आसान हुआ है, banking system को भी ताकत मिली है। GST के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा tax reform किया है। GST ने देश को single market में बदल दिया है और tax base बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद की है।

हमारा infrastructure sector भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में करीब-करीब 10,000 किलोमीटर national highway का निर्माण हुआ है। यानी करीब-करीब 27 किलोमीटर daily निर्माण की गति से काम हो रहा है। ये पहले की सरकारों की तुलना में double है।

रेलवे लाइन के निर्माण में भी दोगुनी गति से काम किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक शहरों में नई मेट्रो, high speed rail project, dedicated trade corridor, इसके लिए भी काम चल रहा है। सरकार 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

अगर मैं aviation sector की बात करूं, भारत में ये सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। इस गति को और तेज करने के लिए देश में करीब-करीब 100 नए एयरपोर्ट और helipad बनाने पर काम किया जा रहा है। उड़ान योजना के माध्यम से देश के tier 2, tier 3 शहरों में हवाई connectivity मुहैया कराने की कोशिश जारी है। भारत

में 100 से ज्यादा national waterways बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

साथियो, इनके अलावा आज भारत में housing for all, power for all, clean fuel for all, health for all, banking for all, जैसी अलग-अलग अनेक योजनाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ तेज गति से बढ़ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में आपके लिए, देश-विदेश के निवेशकों के लिए, भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है।

अभी हाल ही में शुरू की गई 'आयुष्मान भारत योजना' की वजह से भी भारत में medical sector में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बनी है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में tier 2, tier 3 शहरों में नए अस्पताल बनेंगे, medical colleges बनेंगे, paramedical human resource development institutions बनेंगे, paramedical infrastructure मजबूत होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को, उस परिवार को पांच लाख रुपये तक health insurance assurance प्राप्त हो रहा है। मतलब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, उसकी total जनसंख्या से ज्यादा लोगों को benefit मिलेगा। पूरे यूरोप की जो जनसंख्या है, उससे ज्यादा लोगों को benefit मिलेगा। अब ये benefit देने के लिए कितने अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, कितने डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। कितना बड़ा investment की संभावना है और patient के लिए payment अभी से ready है, and इसलिए investment करने वाले के लिए भी return का assurance है। ये अपने-आप में health sector में भारत में पूंजी निवेश का एक बड़ा अवसर आया है, जो tier 2, tier 3 cities में उत्तम स्तर के अस्पताल बनाने की संभावना बनाता है।

साथियो, आज भारत में infrastructure पर जितना खर्च किया जा रहा है, पहले कभी नहीं किया गया। इस वजह से निवेश की अपार संभावनाओं के साथ ही रोजगार के भी लाखों नए अवसर बन रहे हैं। Potential, policy और performance, यही progress का सूत्र है।

New India investment का बेहतरीन destination है और Destination Uttarakhand इस पृष्ठ का एक चमकता हुआ हिस्सा है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में है, जो New India हमारे demographic dividend को represent करते हैं। आज का उत्तराखंड युवा है, आकांक्षाओं से भरा है, ऊर्जा से ओत-प्रोत है। यहां मौजूद असीम संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए त्रिवेन्द्र रावत की सरकार में समझता हूं, भरसक प्रयास कर रही है। Destination Uttarakhand का ये मंच इन्हीं प्रयासों की अभिव्यक्ति है। अब महत्वपूर्ण ये है कि इस मंच पर जो बातें हुई हैं, जो विश्वास प्रकट किया गया है, जो उत्साह प्रकट किया गया है; वो जल्द ही जल्द जमीन पर उतरे। जिससे उत्तराखंड के युवा साथियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले।

साथियो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उत्तराखंड बनाने का फैसला लिया था, तब स्थितियां बहुत मुश्किल थीं। राजनीतिक अस्थिरता के साथ-साथ बेहतर भविष्य के लिए पहाड़ जितनी चुनौतियां भी हमारे सामने थीं। लेकिन आज उत्तराखंड विकास की पटरी पर तेज गति से दौड़ रहा है।

बीते चार वर्षों में micro small and medium enterprises यानी MSME, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योगों को higher credit, support capital, interest subsidy, lower tax और innovations पर ध्यान दिया जा रहा है। हाल में सरकार ने फैसला लिया है- अब MSME के लिए एक करोड़ रुपये तक का ऋण बहुत ही कम समय में स्वीकृत हो जाएगा।

उत्तराखंड में किसी भी project की clearance को लेकर निवेशक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए अनेक व्यवस्थाओं को online किया गया है। परिवेश, इस परिवेश नाम से online forest clearance के लिए एक portal काम कर रहा है, जिससे प्रक्रिया आसान तो हुई है, तेज भी हुई है।

बीते चार वर्षों के दौरान उत्तराखंड में connectivity बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। Highway, railway, airway, हर प्रकार से उत्तराखंड को connect किया जा रहा है। गांव-गांव में पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, चार धाम all weather road और ऋषिकेश- कर्णप्रयागरेल लाइन का काम तीव्र गति से चल रहा है।

साथियो, बेहतर connectivity का सबसे बड़ा लाभ यहां के tourism sector को मिलने जा रहा है। प्रकृति ने तो इस राज्य को समृद्ध किया ही है, साथ में आस्था और संस्कृति का भी वरदान दिया है।

Nature हो, adventure हो, culture हो या फिर योगा, meditation हो, Uttarakhand tourism का एक complete package है, एक आदर्श गंतव्य है। अब तो उत्तराखंड सरकार ने अलग tourism policy बनाकर पर्यटन को industry का status दे दिया है, उद्योग का दर्जा दे दिया है। 18 सालों में पहली बार 13 जिलों में नए 13 destination, tourist destinations को identify करके develop करने की पहल की गई है। इससे निश्चित रूप से राज्य के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे।

साथियो, उत्तराखंड में organic state बनने की पूरी संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि cluster based organic farming के तहत राज्य को organic state बनाने की दिशा में काम काम शुरू कर दिया गया है। Organic farming को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार भी अनेक प्रयास कर रही है।

साथ ही देश में food processing को भी महत्व दिया जा रहा है। Food processing sector को मजबूत करने के लिए सरकार ने food processing में hundred percent 100 प्रतिशत foreign direct investment को, FDI को भी मंजूरी दे दी है। Food processing के मामले में भी आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। चाहे अन्न का उत्पादन हो, फल और सब्जी का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो; अनेक क्षेत्रों में भारत दुनिया में पहले तीन स्थानों में है। हमारे किसानों की पैदावार waste न हो, उनको उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए Food processing पर हमारा focus है। इसमें भी उत्तराखंड का भविष्य स्वर्णिम है।

मैं आप सभी से agriculture में, agri-business में निवेश और बनाने का विशेष आग्रह करूंगा। Agriculture में होने वाला value addition किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। और मैं मानता हूँ कि हम जितना ज्यादा investment, private investment, agriculture sector में करेंगे, हम processing हो, value addition हो, cold storage हो, warehousing हो, transportation के लिए विशेष टाइप के स्पेशल टाइप के carriages हों, ये सारी संभावनाएं हिन्दुस्तान की ग्रामीण economy की ताकत, और जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को एक नया आयाम देने की संभावनाओं से भरी पड़ी है।

साथियो, आज renewable energy के मामले में भारत world leader बनने की तरफ अग्रसर है। दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत आज हिन्दुस्तान में है। हमने तय किया है कि twenty-thirty तक, 2030 तक हमारी 40 प्रतिशत बिजली की क्षमता non fossil fuel based संसाधनों से पैदा होगी। इतना ही नहीं, twenty-twenty two, 2022, जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक 175 GW renewable energy का लक्ष्य ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी solar power का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। International Solar Alliance यानी ISA के पीछे भी यही अवधारणा है। दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हों और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारा तो एक ही मंत्र है- One World, One Sun, One Grid. उत्तराखंड में भी renewable energy के प्रसार के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। Hydel power तो इस राज्य की ताकत है ही, अब solar energy जैसे नए माध्यम की शक्ति जुड़ जाने से उत्तराखंड energy surplus state बनने की पूरी क्षमता रखता है। उत्तराखंड हिन्दुस्तान को ऊर्जावान बना सकता है, इतना potential उत्तराखंड में पड़ा हुआ है।

साथियो, बीते चार वर्षों में Make In India एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है। हमारा आग्रह है Make In India, not only for India but for the whole world. दुनिया ने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है, जिसके चलते information technology के साथ-साथ अब electronic manufacturing का भी भारत hub बनता जा

रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी mobile phone manufacturing unit, उसके साथ-साथ 120 से अधिक फैक्टरियां भारत में काम कर रही हैं। दुनिया के अनेक बड़े ब्रांड आज Make In India का हिस्सा हैं।

वहीं automobile sector में भी भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इस event में जापान उत्तराखंड का पार्टनर है। दोस्तों आपको जान करके खुशी होगी, जापान की कंपनी, जापान के प्रॉडक्ट; वो कार आज हिन्दुस्तान में बनती है और उस कार को जापान import करता है।

साथियो, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को इन तमाम sectors में निवेश करने, उत्तराखंड और New India की growth story का हिस्सा बनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं।

मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दो दिनों में जो MOU sign होंगे, वो बहुत ही शीघ्र फलीभूत भी होंगे और मुझे विश्वास है भारत की प्रगति हमारे राज्यों के potential को maximum उसको अगर channelize करें तो इस देश की विकास यात्रा को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये खुशी की बात है कि आज राज्यों के बीच एक तंदुरुस्त स्पर्धा आरंभ हुई है। हर राज्य दूसरे राज्य से आगे बढ़ना चाहता है, innovative करना चाहता है। अपने राज्य की क्षमताओं के आधार पर करना चाहता है। और जब राज्य अपनी क्षमताओं को ले करके चलता है तो मैं नहीं मानता हूं वो राज्य पीछे होता है। दुनिया के कई देशों से हमारे राज्यों की ताकत ज्यादा है, हमारे राज्यों का सामर्थ्य ज्यादा है। दुनिया के कई छोटे देशों की तुलना में हमारे राज्यों में potential बहुत पड़ा हुआ है।

हर राज्य सपना देखे, मुझे बराबर याद है मैं पहली बार जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना और वो भी 7 अक्टूबर थी, 2001, अभी मेरा तो कोई अनुभव नहीं था, मैं सरकार क्या होती है कुछ जानता नहीं था, मैंने कोई दफ्तर नहीं देखा था, बिल्कुल नया था। पत्रकार पहुंच गए, वो मुझे नोचने लगे। कोई ऐसी गलती कर दूं, ऐसा कोई जवाब दे दूं ताकि मेरा take off हीन हो जाए, भरपूर कोशिश चल रही थी। तो मुझे पूछा गया कि आप ये, आप गुजरात बनाना चाहते हैं, आपका आदर्श कौन है, किसको देख करके आप ऐसा बनाना चाहते हैं। आमतौर पर कोई ऐसा पूछे तो लोगों को लगता है कि ये जवाब आएगा, मैं अमेरिका जैसा बनाना चाहता हूं, इंग्लैंड जैसा बनाना चाहता हूं, ऐसा ही आएगा जवाब। मैंने उनको अलग जवाब दिया, मैंने कहा मैं इसे साउथ कोरिया जैसा बनाना चाहता हूं। तो उनको कुछ मालूम ही नहीं था। फिर मैंने कहा, अपना कैमरा बंद कीजिए, मैं आराम से समझाता हूं, आपको तकलीफ न हो। मैंने कहा गुजरात की जनसंख्या साउथ कोरिया की जनसंख्या समान है। वहां का समुद्री तट, हमारा समुद्री तट, वहां की विकास यात्रा का मैप, यहां की विकास यात्रा का मैप, मैंने कहा मैंने इतना बारीकी से study किया है कि मुझे लगता है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं।

मैं मानता हूं हिन्दुस्तान के हर राज्य में ये ताकत पड़ी है। वो दुनिया के ऐसे कई देशों से मुकाबला करके आगे निकल सकते हैं। अगर हिन्दुस्तान का एक-एक राज्य इस सामर्थ्य के साथ आगे निकल सकता है, हमारे नौजवानों में वो ताकत है, सामर्थ्य है जी।

अभी परसों Russia के राष्ट्रपति यहां थे, पहले हमने एक अलग सा कार्यक्रम किया। वहां एक education institute से उनका बड़ालगाव है, मुझे देखने के लिए ले गए थे। तो मैंने उनको आग्रह किया था, उन बच्चों को एक बार हिन्दुस्तान लाइए। और मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान से भी बच्चों को कभी मैं आपके यहां भेजूं। तो वो इस बार आए थे तो 20 बच्चों को लेकर आए थे। भारत के बच्चे और उनके बच्चे, 20-20 बच्चे, पांच-छह दिन साथ में काम किया। और पांच-छह दिन के भीतर-भीतर Russian mind और Indian mind के बच्चों ने मिल करके ऐसी कमाल की चीजें बनाई थीं, मैं और Russia के राष्ट्रपति उसको देख करके हैरान हो गए कि कितना potential है हमारे बच्चों में। उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको exposure मिलना चाहिए। आज उत्तराखंड ने उस काम में एक कदम बढ़ाया है।

18 साल की उम्र का बड़ा महत्व होता है। उत्तराखंड चिर-पुरातन है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की उम्र 18 साल है। 18 साल की ऊर्जा, 18 साल के सपने, 18 साल का अपना एक कुछ नया कर गुजरने का इरादा अद्भुत होता है। ये उत्तराखंड का काम है कि इस 18 साल को बेकार न जाने दे, ये बड़ा मूल्यवान समय है।

आर्थिक विकास की दुनिया में Special Economic Zone, SEZ, ये हम कई दशकों से सुनते आए हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक अलग SEZ है और सदियों की हमारे ऋषि-मुनियों की तपस्या के कारण, माँगंगा के कारण है, देवाधिदेव हिमालय के कारण है। और वो ऐसी जगह है Spiritual Eco Zone और ये Special Economic Zone से Spiritual Eco Zone की ताकत लाखों गुना ज्यादा है। उत्तराखंड ने उस पर भी ध्यान केन्द्रित करके अपनी योजनाओं का विस्तार और विकास करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि रावत जी के नेतृत्व में ये 18 साल की सरकार, 18 साल की ऐसी ऊर्जावान उम्र में ये राज्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और 2025 में जब आप 25 वर्ष मनाते होंगे, तब आपके सारे सपने साकार हुए होंगे। एक शुभ शुरूआत इस महाभगीरथ प्रयास से हुई है। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और भारत सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसका विश्वास दिलाता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/अभिवन प्रसून/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1548877) आगंतुक पटल : 257

प्रधानमंत्री कार्यालय

चौथी औद्योगिक क्रांति केन्द्र की शुरुआत के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 11 OCT 2018 8:00PM by PIB Delhi

World Economic Forum के प्रेसिडेंट Mr. Borge Brende (बोर्गे ब्रेंडे), उद्योग जगत के सम्मानित सदस्य, देश-विदेश से आए अन्य अतिथिगण, और मेरे साथियों,

आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही सुखद है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मुझे भारत के पहले और विश्व के चौथे Centre of the Fourth Industrial Revolution के शुभारंभ पर याद किया।

साथियों, 'इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो' सुनने में पहली बार लगता है कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके जो कंपोनेंट हैं, जो इसकी ताकत है, वो मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है।

आज के वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह disruptive, interconnected technologies का उदय हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। अलग-अलग technologies के बीच ये सामंजस्य-समन्वय Fourth Industrial Revolution या चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार बन रहा है। इन technologies के अलग-अलग आयाम, पूरी दुनिया में, हर स्तर, हर समाज में लोगों के रहने का तरीका, कार्य करने का तरीका, संवाद का तरीका, लगातार बदल रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद अब भारत में इस महत्वपूर्ण सेंटर का खुलना, भविष्य की असीम संभावनाओं के द्वार खोलता है। मैं World Economic Forum को इस पहल के लिए बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

Fourth Industrial Revolution को कैसे विस्तार मिल रहा है, कैसे ये दुनिया भर में अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। आप इसके एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बारीकियों को समझते हैं।

इसकी महत्ता से आगे बढ़कर आज हम सभी के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है, कि ये Revolution भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों भारत में आज पूरा सामर्थ्य है इस Revolution का पूरा लाभ उठाने का, इससे जुड़ी तमाम तकनीकों को पूरी क्षमता के साथ लागू करने का।

Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, Block chain, Big Data और ऐसी तमाम नई तकनीकों में भारत के विकास को नई ऊँचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है।

भारत की युवा ऊर्जा, Information Technology के क्षेत्र में उसका दशकों का अनुभव, स्टार्ट-अप्स का Vibrant Ecosystem, इस क्षमता को और बढ़ाता है।

आज जब भारत, न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने सामर्थ्य और संसाधनों को मजबूत कर रहा है, तो उसे Fourth Industrial Revolution का साथ मिलना, सोने पर सुहागे की तरह हो गया है।

भारत इसे सिर्फ इंडस्ट्री में परिवर्तन के तौर पर नहीं, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन के आधार के तौर पर देख रहा है। Industry एक Platform है, Production एक Process है, और Technology एक Tool है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य, समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के जीवन को आसान बनाना है, उसमें बदलाव लाना है।

साथियों, मैं इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो में वो ताकत देख रहा हूं, जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी अनेक कमजोरियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, भारत में एक Irreversible Positive Change लाएगी।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो का इस्तेमाल करके भारत की गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। देश के गरीब-वंचित वर्ग को, समाज के उपेक्षित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में जिस Speed और Scale से काम करने की जरूरत है, उसमें ये Revolution हमारी बहुत मदद करेगा।

साथियों, बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। 'इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो' की सफलता भी इसी पर टिकी है कि किस देश में इसके लिए आवश्यक नींव तैयार है, सबसे मजबूत है। आज मुझे गर्व है कि पिछले चार-साढ़े साल में हमारी सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मेरे इस आत्मविश्वास के पीछे, इस उत्साह के पीछे जो वजह है, उसे भी आपके सामने मैं विस्तार से रखना चाहता हूं।

भाइयों और बहनों, इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो में से सिर्फ एक शब्द निकाल दीजिए, तो उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये शब्द है डिजिटल। लेकिन यही शब्द आज बदलते हुए भारत की बड़ी पहचान है। डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांव-गांव तक पहुंचा दिया है।

पिछले चार-साढ़े चार वर्षों में देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश किया है।

साथियों,

- 2014 में भारत के 61 करोड़ लोगों के पास Digital Identity थी। आज भारत के 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, अपनी डिजिटल पहचान है।
- 2014 में भारत में 8 लाख से कम Mobile Based ट्रांसीवर स्टेशन थे। आज इनकी संख्या 18 लाख से ज्यादा हो चुकी है।
- 2014 में भारत में Overall Tele-Density 75 प्रतिशत थी। आज ये भी बढ़कर 93 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है।
- 2014 में भारत में Mobile Internet Subscriptions की संख्या 23 करोड़ थी। आज ये भी बढ़कर दोगुने से ज्यादा, यानी करीब 50 करोड़ पहुंच चुकी है।
- भारत में पिछले 4 साल में इंटरनेट कवरेज 75 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है। इन वर्षों में भारत सरकार ने तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है।

इसी का परिणाम है कि जहां 2014 से पहले सिर्फ देश की 59 पंचायतें ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं, आज एक लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। बहुत जल्द हम देश की सभी ढाई लाख पंचायतों को इस फाइबर से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं।

साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 83 हजार कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में, दूर-दराज वाले इलाकों में सरकार 32 हजार से ज्यादा Wi-Fi Hot Spots मुहैया कराने पर काम कर रही है।

डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 4 वर्षों में भारतीयों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। साथियों ये सब इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो ही है कि

- 2014 में एक भारतीय नागरिक जितने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता था, आज उससे 30 गुना से भी ज्यादा मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहा है।
- ये भी दिलचस्प है कि आज जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा Mobile Data Consumption भारत में हो रहा है, वहीं पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा भी भारत में ही उपलब्ध है।

- इसकी वजह है कि 2014 के बाद से भारत में मोबाइल डेटा की कीमत में 90 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है।

साथियों, ऐसी ग्रोथ स्टोरी आपको दुनिया के किसी देश में सुनने को नहीं मिलेगी। भारत की ये Success Story अप्रत्याशित है।

आज भारत दुनिया के सबसे विशाल Digital Infrastructure वाले देशों में से एक है। आधार, Unified Payments Interface यानि UPI, e-Sign, e-National Agriculture Market यानि e-NAM, Government e-Marketplace या GeM (जेम), Digilocker जैसे Unique Interfaces, भारत को Artificial Intelligence के माध्यम से Technology Leader बनने में मदद कर रहे हैं। इनकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग, तेजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं।

भारत के Digital Infrastructure ने देश के स्टार्ट-अप्स को भी इन प्लेटफॉर्म पर Innovate करने का मौका दिया है। ये Innovations, देश के MSME सेक्टर को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं।

साथियों, भारत में Artificial Intelligence पर Research से जुड़ा Robust Ecosystem तैयार करने के लिए National Strategy कुछ महीने पहले ही बनाई जा चुकी है। सबका साथ-सबका विकास के विजन पर चलते हुए इसे 'Artificial Intelligence For All' का नाम दिया गया है।

कैसे Research Ecosystem बनाया जाएगा, Adoption को Promote किया जाएगा, Skilling Challenges से निपटा जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। विशेष ध्यान उन सेक्टरों पर दिया गया है जो भारतीय जनमानस से सीधे जुड़ते हैं। जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनेक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। इसी कड़ी में पिछले दिनों मोबिलिटी पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई है।

साथियों, मुंबई में WEF का ये नया सेंटर इस कड़ी को और मजबूत करने का काम करेगा। ये सेंटर सबका साथ-सबका विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रेरक और पूरक की तरह काम करेगा।

ये सेंटर नई-नई उभरती Technologies के इर्द-गिर्द सरकार की नीतियों को डिजाइन करने में मदद करेगा। ये सेंटर भारत के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विभिन्न राज्य सरकारों के काम में नई चेतना जगाने, इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो के नए आयामों को आगे ले जाने में मदद करेगा।

मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इस सेंटर ने Drones और Internet of Things के माध्यम से government services को सुधारने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं यहां उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर राज्य में ऐसी अनेक परियोजनाएं शुरू होंगी।

साथियों, भारत में 'इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो' की मजबूती से, 'Artificial Intelligence' के विस्तार से,

जहां एक तरफ देश के लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं इलाज पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा।

कृषि क्षेत्र में इसका विस्तार होने से एक तरफ किसानों की उपज बढ़ेगी, अनाज की बर्बादी रुकेगी तो दूसरी तरफ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये तकनीक भारत के किसानों को मौसम, फसल और बीज बोने के चक्र के संबंध में सही फैसला लेने में मदद कर सकती है।

ये स्मार्ट सिटी और भारत में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही देश के गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद कर सकती है।

स्मार्ट मोबिलिटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और शहरों में जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी नई तकनीकों से भारत को सहायता मिलने वाली है।

हमारा देश भाषाई विविधता से संपन्न है। Artificial Intelligence की मदद से अलग-अलग बोलियों और भाषाओं में विचारों का आदान-प्रदान और आसान हो सकता है।

ऐसे ही भारत के मेरे दिव्यांग भाई-बहनों के सामर्थ्य को और मजबूत करने में, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करने में भी Artificial Intelligence की बहुत बड़ी भूमिका है, उसके अनेक उपयोग हैं।

साथियों, इन सभी प्रमुख विषयों में, अलग-अलग स्तर पर भारत में काम शुरू हो चुका है। इन कार्यों में 'Solve for India, Solve for the World' का लक्ष्य भी समाहित है।

हम 'Local Solution से Global Application' की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजीकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये है Blockchain. ये टेक्नोलॉजी Minimum Government Maximum Governance के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है।

इसकी मदद से self-governance और self-certification को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

तमाम सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की Ease of Living पर पड़ेगा।

साथियों, Blockchain टेक्नोलॉजी का विस्तार, **भारत को Ease of Doing Business Rankings में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है।** सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी से किया जा सकता है।

यही समझते हुए भारत में Blockchain पर भी National Strategy बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिलने वाली है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि भारत बहुत जल्द ही अपनी Drones policy का भी ऐलान करने वाला है।

साथियों, जब पहली औद्योगिक क्रांति हुई, तो भारत गुलाम था। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तो भी भारत गुलाम था। जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई, तो भारत स्वतंत्रता के बाद मिली चुनौतियों से ही निपटने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब 21वीं सदी का भारत बदल चुका है।

मैं आज पूरे विश्वास से, अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान, पूरे विश्व को चौकाने वाला होगा। अभूतपूर्व-अप्रत्याशित-अकल्पनीय योगदान।

हमारी विविधता, हमारा demographic potential, fast-growing market size और digital infrastructure, भारत को Research और implementation का global hub बनाने की क्षमता रखता है। भारत में होने वाले Innovations का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा।

साथियों, आज इस मंच पर मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। कुछ लोग चिंता करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ये उत्थान, रोजगार कम कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मानव जीवन की जिन वास्तविकताओं को हमने आज तक छुवा तक नहीं है, उसके द्वार अब 'इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो' द्वारा खुलेंगे। ये Nature of Job को काफी हद तक बदल देगा।

इस वास्तविकता को समझते हुए ही भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। हमारे देश का युवा बदलती हुई तकनीकों के लिए तैयार हो सके, उस पर पहले से काम किया जा रहा है।

साथियों, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, ये इस हॉल में बैठा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। ये भी कोई नहीं बता सकता कि पांचवी औद्योगिक क्रांति अब कितनी दूर है। ठीक है, पहले की तीन औद्योगिक क्रांति लगभग सौ साल के अंतराल पर आईं। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि चौथी क्रांति ने 30-40 साल पहले ही दस्तक दे दी है।

पिछले एक दो दशक को ही देखें तो अनगिनत चीजों का अविष्कार हुआ और वो लुप्त भी हो गईं। टेक्नोलॉजी ने समय को जैसे squeeze कर दिया है। **इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो से फाइव प्वाइंट जीरो का बदलाव अब 100 साल नहीं लेगा।**

इसलिए, भारत इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो को लेकर इतना गंभीर है। यही समय है, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जुट जाने का। मैं ये भी चाहूंगा कि हम आने वाले कुछ महीनों में ही भारत में एक **‘इंडस्ट्री फोर प्वाइंट जीरो’** पार्क भी स्थापित करें।

मैं आप सभी का, देश के उद्योग जगत का, सभी राज्य सरकारों का, सिविल सोसायटी का, आंत्रप्रन्योर्स का आह्वान करता हूँ कि इस क्रांति में साथ आएँ, साथ जुटें और इसे मिलकर धरातल पर उतारें।

साथियों, हमारी सरकार की सोच खुली हुई है, विचार खुले हुए हैं। जो भी फ्रेमवर्क बनाना हो, जो भी प्रोटोकॉल तय करना हो, जो भी पॉलिसी बनानी हो, नए भारत के हित में, भारतीयों के हित में जो कुछ भी करना हो, हम करेंगे।

आपके हर सुझाव, आपके हर अनुभव का हम हमेशा स्वागत करते हैं। सरकार हर समय, तैयार है, तत्पर है। हम ये ठानकर बैठे हैं कि अब इस बार भारत को चूकने नहीं देंगे।

मैं एक बार फिर आप सभी को Centre of the Fourth Industrial Revolution के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद !!!

अतुल तिवारी/ शाहबाज हसीबी/सतिश/निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1551039) आगंतुक पटल : 166

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Marathi , Assamese , Tamil

प्रधानमंत्री कार्यालय

कारपेट एक्सपो, वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 21 OCT 2018 9:10PM by PIB Delhi

नमस्कार।

वाराणसी में उपस्थित मंत्रीपरिषद की मेरी सहयोगी स्मृति ईरानी जी, Carpet Sector से जुड़े सभी उद्यमीजन, मेरे बुनकर भाई-बहन, और वहां मौजूद अन्य सभी महानुभाव। काशी की पावन धरती पर देशभर से जुटे, विदेशों से आए, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि दुनिया के करीब 38 देशों के ढाई सौ से अधिक अतिथि इस Expo का हिस्सा हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य राज्यों से भी Carpet Sector से जुड़े लोग वहां पहुंचे हैं। आप सभी का बनारस में बनारस के सांसद के नाते भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

साथियो, देश में आजकल त्योहारों का मौसम है। दशहरे, दुर्गापूजा के बाद मुझे पहली बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनारस से जुड़ने का मौका मिला है। अब आप सभी धनतेरस और दीपावली की तैयारी में जुटे होंगे। ये साल का वो समय होता है जब आप सभी, सबसे अधिक व्यस्त होते हैं। इसमें आम दिनों की तुलना में काम जरा अधिक रहता है, क्योंकि मांग ज्यादा होती है। आपके श्रम का, कला का पुरस्कार आपको मिले; इसके लिए भी ये सबसे उत्तम समय होता है।

साथियो, वाराणसी और यूपी के बुनकर और व्यापारी भाई-बहनों के लिए तो इस बार के त्योहार दोहरी खुशियां ले करके आए हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहली बार **India Carpet Expo** हो रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। अब दिल्ली के साथ-साथ वाराणसी में भारत के कारपेट उद्योग को, हमारे बुनकरों को, डिजाइनरों को, व्यापारियों को, अपना कौशल, अपने उत्पादन दुनिया के सामने दिखाने का अवसर मिल रहा है।

साथियो, मुझे खुशी है कि जिन लक्ष्यों को ले करके दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया था, उन लक्ष्यों की तरफ हम तेज गति से बढ़ रहे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र बुनकरों का, कारपेट उद्योग का Hub है। यहां देश के हस्तशिल्प से जुड़े करीब एक-चौथाई बुनकर, श्रमिक और कारोबारी बहन-भाई रहते हैं। वाराणसी हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो; ये कारपेट उद्योग के सेंटर रहे हैं, और अब पूर्वी भारत, ये पूरा क्षेत्र देश के textile export का भी Global Hub बन रहा है। इतना ही नहीं, दीनदयाल हस्तकला संकुल भी Handicrafts के मामले में इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

साथियों, सरकार का निरंतर यही प्रयास है कि हस्तशिल्प छोटे और मझले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए टेक्नोलॉजी से ले करके प्रचार और प्रसार को बल दिया जाए, सुविधाओं को वहां पहुंचाया जाए जहां पर product बनता है। इस बार वाराणसी में हो रहा ये India Carpet Expo इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम तो है ही, साथ में Textile Sector के लिए हमारे Five App के vision का भी अहम स्तंभ है। और जब मैं Five App कहता हूं तो Five App का मतलब है Farm to Fiber, Fiber to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign ये किसान और बुनकर को सीधे दुनियाभर के मार्केट से जोड़ने की तरफ एक बहुत बड़ा प्रयास है।

आने वाले चार दिनों के दौरान इन Expo में एक से एक उत्कृष्ट डिजाइनों का प्रदर्शन होगा, करोड़ों-करोड़ों रुपयों का व्यापार होगा, समझौते होंगे, बिजनेस के नए अवसर खुलेंगे, बुनकरों को नए ऑर्डर मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि विदेशों से जो व्यापारी साथी आए हैं, वो भी हमारी संस्कृति, काशी और भारत के बदले हुए व्यापारिक माहौल का

अनुभव ले पाएंगे।

साथियो, हस्तशिल्प को लेकर भारत में एक बहुत लम्बी परम्परा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी सूत कातने में हथकरघे की बड़ी व्यापकता है। बनारस की धरती का तो इसमें और भी अहम रोल रहा है। बनारस की जितनी पहचान संत कबीर से जुड़ी है, उतनी ही हस्तशिल्प से भी जुड़ी है। संत कबीर सूत भी कातते थे और उसके जरिए जीवन का संदेश भी देते थे। कबीरदास जी ने कहा है-

कहि कबीर सुनो हो संतो, चरखा लखे जो कोय।

जो यह चरखा लखि भए, ताको अवागमन न होय।।

यानी चरखा ही जीवन का सार है और जिसने इसे समझ लिया, उसने जीवन का मर्म भी समझ लिया। जहां हस्तशिल्प को जीवन के इतने बड़े दर्शन से जोड़ा गया हो वहां बुनकरों के जीवन को सरल बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब बनती हैं तब संतोष का एक भाव आता है।

साथियो, हमारे देश में हस्तशिल्प- व्यापार, कारोबार से भी ऊपर प्रेरणा का, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का, स्वावलंबन का माध्यम रहा है। गांधीजी, सत्याग्रह और चरखे का हमारे आजादी के आंदोलन में क्या महत्व रहा है, ये हम भलीभांति जानते हैं।

हस्तशिल्प के माध्यम से स्वावलंबन के इस संदेश को मजबूती देने के लिए आप सभी के सहयोग से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट उत्पादक देश है। बीते चार-साढ़े चार वर्षों से तो हाथ से बने कालीन के मामले में हम दुनिया में टॉप पर हैं। ये लाखों बुनकरों, डिजाइनरों, व्यापारियों के श्रम, और सरकार की नीतियों के चलते संभव हो पाया है।

साथियो, आज दुनियाभर के carpet market का एक-तिहाई से भी अधिक यानी 35 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है और आने वाले दो-तीन वर्षों में ये बढ़कर 50 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। यानी आने वाले सालों में दुनिया में carpet का जितना भी कारोबार होगा, उसका आधा हिस्सा भारत के पास होगा, आप सभी के पास होगा।

पिछले वर्ष हमने 9 हजार करोड़ रुपये के कालीन निर्यात किए। इस वर्ष करीब 100 देशों को हमने कारपेट निर्यात किए हैं। ये प्रशंसनीय कार्य है लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि 2022 तक, जब हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे, तो हम निर्यात के इस आंकड़े को ढाई गुना से भी अधिक, 25 हजार करोड़ रुपये तक ले जाएं।

सिर्फ निर्यात ही नहीं बल्कि देश में भी कालीन कारोबार में बीते चार वर्षों के दौरान तीन गुना से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। चार वर्ष पहले जो बाजार 500 करोड़ का था, वो आज 1600 करोड़ का बन चुका है।

देश में कालीन मार्केट का दायरा अगर बढ़ा है तो उसके लिए, उसके पीछे दो स्पष्ट कारण हैं। एक तो, देश में मध्यम वर्ग का लगातार विस्तार हो रहा है और दूसरा, कालीन उद्योग के लिए, उसके प्रचार-प्रसार के लिए अभूतपूर्व सुविधाएं दी जा रही हैं।

साथियो, इस ट्रेंड को लेकर ही हम चलें तो कालीन उद्योग का, पूरे textile sector का भविष्य देश में उज्ज्वल है। आज भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा carpet बनाता है। इतना ही नहीं, भारत के carpet, कला और शिल्प के मामले में उत्कृष्ट तो होते ही हैं, ये environment friendly भी हैं। ये आप सभी की मेधा, आपकी skills का ही कमाल है कि दुनियाभर में Made in India Carpet, ये Made in India Carpet एक बड़ा Brand बन करके उभरा है।

साथियो, इस Brand को और मजबूत करने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास के लिए प्रतिबद्ध है। Carpet Exporters को असुविधा न हो, इसके लिए logistic support को और मजबूत किया जा रहा है। देशभर में गोदाम और शोरूम की सुविधा देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे आप एक बड़े मार्केट तक अपने सामान

को आसानी से पहुंचा पाएंगे।

इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को लेकर भी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। भदोई और श्रीनगर में कालीन परीक्षण सुविधा के लिए Indian Institute of Carpet Technology यानी IICT; इसमें विश्वस्तरीय laboratory स्थापित की गई है। कोशिश ये है कि हमारे products, zero defect, zero effect वाले हों, जिसमें खोट बिल्कुल न हो और पर्यावरण की चिंता उत्पाद में भी झलके।

इसके अलावा, कालीन के साथ-साथ हस्तशिल्प के दूसरे सामान की मार्केटिंग और बुनकरों को अन्य सहायता के लिए भी अनेक व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। वहां वाराणसी में ही 9 common facility centre, common service centre बनाए गए हैं। इन सेंटरों का लाभ हजारों बुनकरों को मिल रहा है।

साथियो, गुणवत्ता के अलावा बुनकरों को, छोटे व्यापारियों को पैसे की दिक्कत न हो, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये की गारंटी फ्री ऋण से बहुत बड़ी मदद हो रही है। बुनकरों के लिए तो मुद्रा योजना में 10 हजार रुपये की margin money का भी प्रावधान किया गया है।

इतना ही नहीं, अब जो भी सहायता या कर्ज, बुनकरों का दिया जा रहा है, वह बहुत ही कम समय में सीधा उनके खाते में पहुंच रहा है। 'पहचान' नाम से जो पहचान पत्र बुनकरों को दिया गया है, उससे बिचौलियों को हटाने में बहुत बड़ी मदद मिली है।

इसके अलावा भदोई, मिर्जापुर Mega Carpet Cluster और Srinagar Carpet Cluster बुनकरों को आधुनिक loom भी दिए जा रहे हैं। Loom चलाने का कौशल पैदा हो, इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बुनकरों के कौशल में बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए skill development के अनेक प्रोग्राम चल रहे हैं।

साथियो, पहले जब भी मैं बुनकर भाई-बहनों से बात करता था तो एक बात जरूर सुनने को मिलती थी, वो कहते थे कि हमारे बच्चे अब इस काम में जुड़ना नहीं चाहते हैं। इससे गंभीर स्थिति भला क्या हो सकती है? आज जब हम carpet के मामले में दुनिया के शीर्ष पर हैं, तब आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी उतना ही आवश्यक है।

इसी लक्ष्य के तहत IICT भदोई में, कालीन प्रौद्योगिकी में बीटेक (B.Tech) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रशिक्षण संस्थानों में इस तरह के कार्यक्रम चलाने की योजना है। बुनकरों के कौशल के साथ-साथ उनकी और उनके बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गरीब बुनकर परिवारों के बच्चों की फीस का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है।

साथियो, आपकी कला और श्रम को राष्ट्र की शक्ति बनाने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में देश के लिए, बनारस के लिए इस कला का प्रदर्शन करने के बहुत बड़े अवसर आने वाले हैं।

अगले वर्ष जनवरी में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन काशी में होने वाला है, वो भी प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम साबित होगा। मुझे विश्वास है कि दुनियाभर से आए व्यापारी साथी हमारे हस्तशिल्प के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक स्मृति और बदलती काशी का आनंद भी ले पाएंगे।

एक बार फिर आप सभी को धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए, काशी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मैं मंत्रालय को, मेरे बुनकर भाइयों-बहनों को, export-import से जुड़े हुए सभी महानुभावों को काशी पधारने के लिए, काशी को प्रतिष्ठा के केंद्र में लाने के लिए मैं फिर से एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

अतुल तिवारी/ वंदना जाटव/ निर्मल शर्मा

(रिलीज़ आईडी: 1550193) आगंतुक पटल : 424